● वर्ष-6
● अंक-10
रायपुर, बुधवार
19 अगस्त 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6>> ओम नमः शिवाय से मिलती....

मनुष्य को स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए

पीएम मोदी ने एक्स पर दिया एकजुटता पर जोर

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रेरणादायी सुभाषित साझा किया, जिसमें आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने संस्कृत का श्लोक, उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम्। अप्यपर्वणि भज्येत न नमत्वेव कस्यचित्॥ साझा किया। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि मनुष्य को सदैव अपने आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ और पराक्रम इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे, बल्कि सत्य, धैर्य और आत्मगौरव के साथ अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। यह संदेश राष्ट्र निर्माण में नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत दृढ़ता की भूमिका को रेखांकित करता है।

इससे ठीक एक दिन पहले, सोमवार को भी प्रधानमंत्री ने सुभाषित के माध्यम से सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा था, सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही देश आगे बढ़ता है। यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। इसके साथ ही उन्होंने एक श्लोक, समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ भी साझा किया था, जिसका हिंदी अर्थ है कि हम सबके संकल्प एक समान होने चाहिए, हमारे मन एकता के भाव से जुड़े होने चाहिए, जिससे हम सभी परस्पर सहयोग तथा समान व्यवहार के साथ समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इन संदेशों के जरिए प्रधानमंत्री लगातार समाज में सकारात्मक सोच और सहभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी इसी तरह का प्रेरणादायी सुभाषित साझा किया था। तब उन्होंने उन सभी देशवासियों को हृदय से नमन किया था, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है और सद्भावना तथा एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को सशक्त करने का आग्रह किया था। इस अवसर पर साझा किया गया श्लोक था, उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः। कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति॥ जिसका हिंदी अर्थ है कि परिश्रम, उद्यम और पुरुषार्थ से ही विविध कलाएं, विज्ञान, तकनीकी कौशल, शिल्प तथा नवाचार विकसित होते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यह श्लोक मनुष्य को भाग्य के भरोसे न बैठकर साहस, कर्मठता और निरंतर प्रयास के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है, क्योंकि पुरुषार्थ ही भाग्य का निर्माता है। प्रधानमंत्री के ये सुभाषित सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिगत उत्थान और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं।

राम मंदिर चंदा चोरी मामला : एसआईटी की रिपोर्ट में

चंपत राय और अनिल मिश्रा को क्लीन चिट

नईदिल्ली। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है. चंपत राय के साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट मिली है. मामले की जांच कर रही एसआईटी से अपनी अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, उसे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दी गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम नहीं है.हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की जांच अभी चल रही है.

सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में कुल 8 लोगों के नाम शामिल हैं, जिनको पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. दान चोरी मामले के उजागर होने के बाद से ही चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे. आरोपों के चलते ही दोनों ने ही

ट्रस्ट में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था. अब एसआईटी रिपोर्ट में दोनों को क्लीन चिट मिल गई है. यानी कि जांच एजेंसी ने ये साफ कर दिया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की चंदा चोरी मामले में कोई भूमिका नहीं है। बता दें कि यह रिपोर्ट उस स्क्रुज़ की है, जिसका गठन यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया था. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनाई गई दूसरी स्क्रुक अब भी मामले की जांच कर रही है. योगी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की अंतिम जांच रिपोर्ट को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है.

एफआईआक में इन 8 आरोपियों का नाम

राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की दी गई शिकायत पर दर्ज की गई स्क्रुक्रमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और राम शंकर यादव उर्फ टीनू का नाम है. सभी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यूपीआई पेमेंट पर चार्जः राष्ट्रपति से मिली बिल को मंजूरी

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2026 और भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में संशोधन से जुड़े कानून को मंजूरी दे दी है। इन विधेयकों को संसद ने 10 अगस्त को पारित किया था।

भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन से सरकार को यूपीआइ और रुपे कार्ड लेनदेन पर शुल्क लगाने का कानूनी आधार मिल गया है। सरकार अधिसूचना के जरिये यह तय कर सकेगी कि किन इलेक्ट्रानिक भुगतान माध्यमों या लेनदेन पर 'व्यवसायी रियायती दर' (एमडीआर) शुल्क नहीं लगेगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में कहा था कि यूजर के लिए यूपीआई भुगतान निःशुल्क बना रहेगा और भविष्य में एमडीआर शुल्क कुछ निश्चित श्रेणियों के कारोबारी लेनदेन पर ही लागू होगा।

वहीं, कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम का उद्देश्य विदेशी पूंजी आकर्षित करना, घरेलू इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी क्लाउड कंपनियों के लिए भारतीय डेटा केंद्रों का इस्तेमाल सुगम बनाना है।

पांच जून को लाया गया अध्यादेश

यह कानून पांच जून, 2026 को जारी उस अध्यादेश का स्थान लेता है, जिसके तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की ब्याज आय और पूंजीगत लाभ को आयकर से छूट दी गई थी।

इस अधिनियम में विदेशी कंपनियों के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का अनुबंध विनिर्माण पर कराने को लेकर उपलब्ध आयकर छूट को वित्त वर्ष 2040-41 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, सर्वर और उनके प्रमुख कलपुर्जे एवं सहायक उपकरण शामिल हैं।

भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, रचनात्मकता तथा नवाचार की क्षमता ही विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है। विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप अवसर देकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से व्यापक रूप से जोड़ना होगा। युवाओं को सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों से जोड़ने से उनमें नेतृत्व क्षमता, सेवा भाव, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना मजबूत होगी।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित 'मेरा युवा भारत' (माय भारत) की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बैठक में माय भारत की गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इस मंच से जोड़ने और विभिन्न विभागों की गतिविधियों में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का प्रत्येक युवा विकास की मुख्यधारा से जुड़े और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। इसी उद्देश्य से 'मेरा युवा भारत' जैसे व्यापक मंच की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री युवाओं के विचारों, आकांक्षाओं और गतिविधियों में विशेष रुचि लेते हैं तथा युवा शक्ति को विकसित भारत के संकल्प

का प्रमुख आधार मानते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आज का युवा तकनीक और डिजिटल माध्यमों के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसकी सोच व्यापक है, उसमें नवाचार की क्षमता है और वह तेजी से बदलाव को आत्मसात कर सकता है।

युवाओं की यही ऊर्जा सकारात्मक और राष्ट्रहित के कार्यों में लगे, इसके लिए उन्हें सही दिशा, अवसर और मंच उपलब्ध कराना आवश्यक है। आने वाले वर्षों में यही युवा देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, इसलिए उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करने और सामाजिक सरोकारों से जोड़ने के लिए अभी से सुनियोजित प्रयास किए जाने चाहिए।` स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, खेल, पर्यावरण संरक्षण, सिविक सेंस, इतिहास, पर्यटन, कौशल विकास, कृषि, तकनीकी शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सामाजिक कल्याण सहित विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में युवा शक्ति का सहयोग उपयोगी हो सकता है, वहां माय भारत के माध्यम से उन्हें अवसर दिए जाएं।

प्रमुख समाचार

भाजपा ने तीन राज्यों के प्रभारियों का किया एलान

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को राज्यसभा सदस्य विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश में पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया और नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी बनाया। पार्टी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नवनियुक्त भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया को पंजाब में पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नवीन ने राज्यसभा सदस्य तरुण चुघ को गुजरात में पार्टी मामलों का प्रभारी बनाया है। भाजपा ने एक परिपत्र में कहा, ''ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। अन्य राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति उचित समय पर की जाएगी। तब तक वर्तमान प्रभारी व्यवस्था जारी रहेगी।'' पार्टी सूत्रों के अनुसार, ये नियुक्तियां अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष की शुरुआत में प्रस्तावित हैं। जबकि गुजरात में चुनाव 2027 के उत्तरार्ध में हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की दिल्ली एम्स में सफल एंजियोप्लास्टी

नईदिल्ली। अस्पताल ने पुष्टि की है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एंजियोप्लास्टी हुई और अभी उनकी हालत स्थिर है। एम्स की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त 2026 को एंजियोप्लास्टी हुई और वे कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी में हैं तथा उनकी स्थिति स्थिर है। बेचैनी महसूस होने के बाद, 14 अगस्त को नड्डा को एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती कराया गया था। 13 अगस्त की शाम को कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई टेस्ट करके उनकी जांच की गई थी। एम्स ने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 13 अगस्त 2026 की शाम को बेचैनी के कारण कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई टेस्ट करके जांच की गई थी। वे अभी ठीक हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती हैं।

दिल्ली को फडणवीस की जरूरत पीएम मोदी कर रहे बात : राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने मंगलवार को संकेत दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र सरकार में काम करने के लिए दिल्ली बुलाया जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए राउत ने कहा कि दिल्ली को देवेंद्र फडणवीस की ज़रूरत है, और सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट में संभावित फेरबदल के तहत उनसे सलाह-मशविरा कर रहे होंगे। राउत ने ऐसी राजनीतिक चालों को ट्रायल बैलून बताया और कहा कि भले ही फडणवीस महाराष्ट्र छोड़ने के इच्छुक न हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका ज़रूरी हो सकती है। राउत ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें (पतंग उड़ाना) स्वाभाविक हैं। दिल्ली को देवेंद्र फडणवीस की ज़रूरत है। भले ही फडणवीस दिल्ली जाने के इच्छुक न हों, लेकिन देश उन्हें बुला रहा है। प्रधानमंत्री को एक बेहतरीन कैबिनेट बनानी है, इसीलिए वह देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं।

आप नेता भारद्वाज पर मानहानि मामले की सुनवाई टली

नई दिल्ली । दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा द्वारा दायर मानहानि शिकायत की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है। यह मामला पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल एसएस मोटा सिंह से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट का है। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत और मानहानिकारक बातें कही थीं। उनका कहना है कि इन पोस्ट से उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने यह कदम प्रवेश वर्मा और उनके गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद उठाया। 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा का बयान दर्ज किया गया था, जबकि 15 जुलाई को कुलभूषण जैन और शक्ति सिंह सहरावत के बयान दर्ज किए गए थे। प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मई में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर उन्हें एक पॉक्सो मामले से जोड़ते हुए आरोप लगाए थे। वर्मा के मुताबिक, इन पोस्ट की जानकारी उन्हें दोस्तों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिली, जिन्होंने उन्हें व्हाट्सऐप पर पोस्ट के लिंक भेजे।

मैंने वही वंदे मातरम गाया जो गांधी-नेहरू गाते थे : खरगे

पणजी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को वंदे मातरम को लेकर उठे विवाद पर अपनी बात रखी। खरगे ने कहा कि उन्होंने वही वंदे मातरम गाया है, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी गाते थे।

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, मैंने वही वंदे मातरम गाया, जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने गाया था। अगर इसे गाना अपराध है, तो वे (आरोप लगाने वाले) पिछले 18 साल से यह अपराध करते आ रहे हैं। अगर यह अपराध है, तो गांधी जी के खिलाफ मामला दर्ज करें। अगर यह अपराध है, तो नेहरू जी के खिलाफ मामला दर्ज करें। अगर यह अपराध है, तो वल्लभभाई पटेल के खिलाफ मामला दर्ज करें। उन्होंने आगे कहा, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके जन्म लेने से भी पहले कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके यह तय किया था कि देश के लिए कौन सा राष्ट्रीय गीत अपनाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कहेंगे, वही देश का मानक बन जाएगा। कल कोई दूसरी सरकार सत्ता में आ सकती है। अगर वह कुछ कहेगी, तो क्या वह नियम बन जाएगा?

स्टील फ्रेम का पुनर्निर्माण

शासन करने से लेकर सेवा तक, समयबद्ध सुधारों का सिलसिला

डॉ. जितेंद्र सिंह

जब अंग्रेज 1947 में भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन जाने लगे, तो वे एक मुहावरा अपने पीछे छोड़ गए - स्टील फ्रेम। इसे वे भारतीय सिविल सेवा कहते थे, वह प्रशासनिक ढांचा जिसके जरिए ब्रिटिश राज अपनी हुकूमत चलाता था। स्टील आसानी से नहीं झुकता, और यही वास्तविक बात थी। यह ढांचा एक साम्राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए बनाया गया था, न कि उन लोगों की बात सुनने के लिए जिन पर उसने शासन किया था। आजादी के बाद दशकों तक हमें वो फ्रेम विरासत में मिला। हमने उसे नया नाम दिया, उसे खादी का आवरण पहनाया और खुद को बताया कि अब यह हमारा अपना है। लेकिन नियंत्रण के लिए बनाया गया फ्रेम स्वभाविक रूप से सेवा के लिए बनाया गया ढांचा नहीं है। और हमारे गणतंत्र के पहले कई दशकों तक, भारत अपने उपनिवेशक देश के ढांचे के अंदर ही बना रहा। एक ही फॉर्म को तीन प्रतियों में दाखिल करता रहा, उन्हीं ऊंची कुर्सियों के सामने कतारों में खड़ा होता रहा और अपने भाग्य के फैसले के लिए किसी साहब की प्रतीक्षा करता रहा। मैंने अपने कामकाजी जीवन का अधिकांश समय इस ढांचे के अंदर बिताया है। पहले एक नागरिक के रूप में और एक प्रोफेशनल के रूप में, फिर भारत सरकार में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन का प्रभार सौंपे गए मंत्री के रूप में, जिस विभाग का काम ही स्टील फ्रेम की जांच करना और यह पूछना है कि क्या फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए जब मुझसे पूछा जाता है कि क्या भारत ने अपनी नौकरशाही में सुधार किया है, तो मेरे उत्तर में न तो किसी संस्थान की रक्षा करने वाले व्यक्ति का ढाल बनना है, न ही किसी ऐसे व्यक्ति की निंदा है जिसने इसे छोड़ दिया है। यह एक ऐसे व्यक्ति का उत्तर है, जिसने एक ऐसी प्रणाली के बारह वर्षों के शांत लेकिन दृढ़ पुनर्निर्माण को अंदर से देखा है, जिसे स्वतंत्रता के बाद से सार्थक

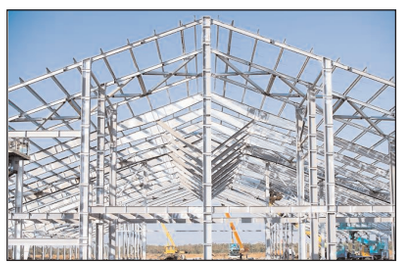

रूप से नहीं छुआ गया था। अगर श्री नरेन्द्र मोदी, जो अपनी पथ-प्रदर्शक सोच के लिए जाने जाते हैं, भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार नहीं संभालते तो शायद अब भी अछूता रह गया होता।

विचार करें कि हमने कहां से शुरुआत की। 2014 में, केंद्र सरकार से एक नागरिक की शिकायत को अगर हल कर लिया गया, तो इसे करने में औसतन 157 दिन लगे। अगर शिकायत दर्ज कर भी ली गई, तो इसका मतलब देश भर में फैले मुश्किल से दस हजार शिकायत अधिकारियों के साथ एक प्रणाली की खोज करना था, जिनमें से अधिकांश तक पहुंच नहीं थी और वे सभी किसी भी वास्तविक समय सीमा के प्रति क ई जवाबदेह नहीं थे। नौकरी के लिए सरकारी कार्यालय के बाहर कतार में खड़ा एक युवक, अपने पति की पेंशन फ़ाइल का पता लगा रही एक विधवा, यह जानने की कोशिश में लगा एक किसान कि उसके फसल बीमा दावे की फाइल किसी मंत्रालय की अलमारी में से क्यों गायब हो गई, इन सबके सामने एक ही स्थिति थी। उनका सामना नागरिकों को प्रतीक्षा कराने के लिए डिज़ाइन की गई एक सिस्टम से और ऐसे अधिकारियों से था, जिनका किसी भी परिणाम के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। यह केवल अक्षमता नहीं थी। यह उस प्रशासन का अंतिम जीवित अवशेष था जिसका निर्माण समाधान उपलब्ध कराने के बजाय डराने के लिए किया गया था। आज के साथ इसकी तुलना राय का विषय नहीं है; यह संख्याओं में वर्णित है। शिकायत निपटान का समय 157 दिन घटकर 15 दिन रह गया है। आज का हमारा सिस्टम नौ गुना अधिक सालाना लगभग 3 लाख से बढ़कर 27 लाख शिकायतों का निवारण करता है। इन शिकायतों का निवारण करने वाले अधिकारियों की संख्या दस गुना से अधिक बढ़कर एक लाख तक पहुंच गई है। इस वर्ष मार्च में ही, केंद्रीय सचिवालय ने लगातार पैंतालीसवें महीने में एक लाख शिकायतों के निवारण के आंकड़े को पार कर लिया है। हमने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली का एक ऐसे प्लेटफॉर्म में निर्माण किया है जो अब 22 भाषाओं में बोलता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके एक नागरिक की शिकायत को सही डेस्क पर ले जाता है। यहां तक कि एक दूरस्थ गांव में एक किसान की आवाज में, उसकी अपनी भाषा में, एक चैटबॉट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। काफी जानबूझकर, हमने इसका नाम समाधान दीदी अर्थात् 'समाधान करने वाली बहन' रखा था। जिस ग्रामीण को अपने काम के लिए कभी जिला कार्यालय की यात्रा करने की आवश्यकता होती थी और उम्मीद करनी होती थी कि उसका काम सरलता से हो जाए, वह अब अपनी पंचायत में एक सामान्य सेवा केंद्र से यह काम कर सकता है। हर महीने की बीस तारीख को सीएससी-सीपीजीआरएएमएस दिवस के रूप में निर्धारित किया जाता है ताकि यह वादा अंतिम मील तक पहुंच सके। लेकिन वह गहरा परिवर्तन, जिसे मैं स्टील फ्रेम का सच्चा सुधार मानता हूं, वह डिजिटल प्लंबिंग नहीं है। यह इस दर्शन में बदलाव है कि हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों का निर्माण कैसे करते हैं। 70 वर्षों तक, सरकार नियम-आधारित संस्कृति पर चलती रही- एक अधिकारी को इस बात से आंका जाता था कि क्या उसने सही प्रक्रिया का पालन किया था, न कि इस बात से कि उसने नागरिक की समस्या को हल किया है या नहीं। 2020 में, हमने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया।

बस्तर के सरकारी स्कूलों खतरे के बीच बच्चों की पढ़ाई

जिले के 100 से ज्यादा स्कूल हुए जर्जर, पंचायत भवन में लग रही क्लास

जगदलपुर। बस्तर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य पर अब जर्जर स्कूल भवनों का खतरा मंडरा रहा है। जिन स्कूलों में बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए वहां कई बच्चे आज बदहाल और अति जर्जर भवनों के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। कई स्कूलों में भवन की खराब स्तिथि के कारण नियमित कक्षाएं संचालित करने के लिए पर्याप्त कमरे तक उपलब्ध नहीं है।

दरअसल, सरकारी आंकड़े इस स्थिति की गंभीरता खुद बयां कर रहे हैं। बस्तर जिले में ही 124 स्कूल भवन अति जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। इनमें 76 प्राइमरी और 48 मिडिल स्कूल भवन शामिल हैं। हालात इतने खराब हैं कि कई स्कूलों में नियमित कक्षाओं के लिए कमरे तक उपलब्ध नहीं हैं। कहीं बच्चों की कक्षाएं अतिरिक्त भवनों में लग रही हैं।उदाहरण के रूप में तोकापाल इलाके के एर्राकोर्ट मिडिल स्कूल अति जर्जर की स्थिति में होने की वजह से पूरी स्कूल पंचायत भवन में संचालित हो रहे हैं, तो कहीं लैब, प्रधानाध्यापक के कार्यालय में बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बारिश के मौसम में परेशानी और बढ़ जाती है। जर्जर भवन, खराब छत और भवनों की गुणवत्ता को लेकर सामने आ रही समस्याओं के बीच सबसे बड़ी चिंता बच्चों की सुरक्षा की है।जिला शिक्षा अधिकारी बलिराम बघेल ने भी माना है कि जिले में 124 विद्यालय भवन अति जर्जर हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इन स्कूलों की कक्षाएं सुरक्षित स्थानों पर संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जर्जर भवनों की जानकारी शासन-प्रशासन को भी भेजी गई है।सवाल अब सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं है। सवाल यह भी है कि बच्चों को कब तक जर्जर भवनों से दूर रखकर पढ़ाया जाएगा और इन स्कूलों के स्थायी समाधान पर कब काम होगा क्योंकि बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना है, तो उनकी पढ़ाई की नींव भी मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए।

न्यूनतम मजदूरी 30 हजार रुंपये, पेंशन 7500, भारतीय मजदूर संघ की मांग

भारतीय मजदूर संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के लेकर केंद्र सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा

बिलासपुर-दुर्ग। भारतीय मजदूर संघ ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में मजदूरों और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर रैली निकाली और केंद्र सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर में सौंपे गए ज्ञापन में मजदूरों और कर्मचारियों से जुड़ी 11 प्रमुख मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की गई है। इनमें श्रक्र-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1100 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये प्रतिमाह करने और इसे आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग प्रमुख है।

इसके अलावा ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस की गणना के लिए अधिकतम वेतन सीमा को दोगुना करने और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग की गई है।न्यूनतम मजदूरी 30 हजार रुपये किया जाए। पेंशन 7500 किया जाए। सरकार निरंकुश है। सरकार को जगाने के लिए ही आए है। संगठन ने ग्रेच्युटी की गणना को 15 दिन के वेतन से बढ़ाकर 30 दिन के वेतन के आधार पर करने, सभी कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन लागू करने और जीवन-यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप न्यूनतम वेतन में वृद्धि की मांग रखी है। ज्ञापन में आंगनबाड़ी, आशा, मिड-डे-मील, एनएचएम सहित विभिन्न योजना कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी, बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने तथा लेबर कोड में मजदूर विरोधी प्रावधानों को हटाने की मांग भी शामिल है।संगठन ने हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन सहित विभिन्न संस्थानों के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और रूग्ण में पदस्थ डेवलपमेंट ऑफिसरों को नौकरी की सुरक्षा देने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपते समय जिला मंत्री संजय कुमार तिवारी सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। देश के श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक हितों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में दुर्ग में भी रैली निकाली गई। राजेंद्र पार्क चौक से शुरू हुई रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां श्रमिक नेताओं ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा और श्रमिकों के बेहतर भविष्य से जुड़े कई मुद्दे शामिल रहे। संघ ने न्यूनतम वेतन 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने, ईएसआईसी की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम 7,500 रुपये पेंशन के साथ महंगाई भत्ता व चिकित्सा सुविधा देने की मांग की। ईपीएफ की अनिवार्य वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने और बोनस की गणना और पात्रता सीमा बढ़ाने की मांग भी रखी गई।

आंगनबाड़ी, आशा और मिड-डे मील कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि, ठेका व कैजुअल कर्मचारियों के लिए समान काम-समान वेतन, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये करने और बैंक कर्मचारियों के लिए पांच दिन कार्य व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। सफाई कामगार मजदूर संघ ने नगर निगम दुर्ग के करीब 1800 सफाई कर्मियों की समस्याओं का निराकरण करने की मांग उठाई। मिशन क्लीन सिटी कर्मचारियों का मानदेय 30 हजार रुपये करने, ईपीएफ ईएसआईसी सुविधा देने और न्यूनतम मजदूरी के अनुसार वेतन देने की मांग की गई।

कावड़ यात्रा के दौरान महिला और बच्चों पर एसिड अटैक

दुर्ग। सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में भक्त शिवजी को जल चढ़ाने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सोमवार को नंदिनी थाना इलाके में बच्चों संग कांवड़ यात्रा पर निकली महिला के ऊपर एसिड अटैक किया गया। एसिड अटैक में महिला और उसके बच्चे झुलस गए। महिला और उसके बच्चों को दुर्ग के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एसिड अटैक करने वाला युवक बाइक से आया और एसिड फेंककर फरार हो गया।घटना नंदिनी थाना इलाके के रवलीडीह और अरसानारा मार्ग पर हुई। महिला अपने बच्चों के साथ कांवड़ लेकर जा रही थी, तभी अज्ञात शख्स बाइक से आया और महिला पर एसिड फेंककर फरार हो गया।

एसिड अटैक में महिला के बच्चे भी आ गए। पीड़ित परिवार का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम महिला और बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला का चेहरा और गला एसिड अटैक से झुलस गया है, जबकि दोनों बच्चे एसिड अटैक में हल्का सा झुलसे हैं।नंदिनी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को खबर मिली की आरोपी युवक करंजा, भिलाई में है। पुलिस ने तत्काल आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की।

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने एसिड अटैक करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि वो महिला को पहले से जानता है और दोनों एक साथ पेंट फैक्ट्री में काम कर चुके हैं।

एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने कहा, पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात मोटर साइकिल सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को खबर मिली की जिस संदिग्ध युवक की तलाश हम कर रहे हैं वो करंजी इलाके में मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उससे घटना के संबंध में पूछताछ की।

कोरबा में टीआई समेत चार पुलिसकर्मी सस्पेंड, आठ की बदली जिम्मेदारी

कोरबा। कोरबा में कटघोरा थाना टीआई एमबी पटेल समेत चार पुलिसकर्मियों को एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने सस्पेंड कर दिया है।साथ ही साथ चार थानों के थानेदार भी बदल दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है सस्पेंशन की कार्रवाई कबाड़ से जुड़ी एक कार्रवाई को लेकर की गई है।जिसमें कबाड़ व्यवसायी के ट्रक को पकड़ने के बाद मामला थाने में दर्ज नहीं किया गया। ये जानकारी जब एसपी तक पहुंची तो उन्होंने इसकी जांच करवाई। जिसमें टीआई एमबी पटेल की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। इस वजह से एसपी ने टीआई समेत चार पुलिसकर्मियों को नाप दिया। सस्पेंशन में टीआई, एक एएसआई, एक हवलदार और एक सिपाही शामिल हैं। इसके अलावा एक अन्य ट्रांसफर आर्डर जारी किया गया है। जिसमें चार थानेदारों के प्रभार में बदलाव किया गया है।यानी चार थानों के टीआई बदले गए हैं। जबकि कुल आठ पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है।

17 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक 3 निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक और 4 सहायक उप निरीक्षक समेत कुल 8 पुलिसकर्मियों की पदस्थापना बदली गई है। सभी अधिकारियों को तत्काल नई पदस्थापना वाले स्थान पर आमद देने के निर्देश दिए गए हैं। कटघोरा थाना में कबाड़ व्यवसायी विजय साहू के कबाड़ लोडेड ट्रक को कुछ दिन पहले पकड़ा गया था। कटघोरा थाना में तैनात पुलिसकर्मी एएसआई राम पांडेय, हवलदार सुरेश तंवर और सिपाही पुष्पेंद्र कुर्रे की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। कबाड़ से लोडेड इस ट्रक को कटघोरा थाने में खड़ा करके रखा गया था। लेकिन इसकी जानकारी ना तो थाने के रिकॉर्ड में दर्ज की गई, ना ही कार्यवाही के लिए कोई एफआईआर दर्ज किया गया।चर्चा है कि इसके एवज में लेनदेन की बातें चल रही थी। कबाड़ व्यवसायी ने अपने सामान को वापस प्राप्त करने के लिए कोर्ट में सुपुर्दनामा का आवेदन लगाया।तब यह बात सामने आई कि थाने में कोई कार्यवाही ही नहीं हुई है। बात एसपी तक पहुंच गई, जांच के आदेश दिए गए। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सोमवार के देर शाम एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने टीआई एमबी पटेल सहित सहायक उप निरीक्षक राम पांडेय, हवलदार सुरेश तंवर और सिपाही पुष्पेंद्र कुर्रे को सस्पेंड कर दिया। कटघोरा थाने में पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के साथ ही एसपी ने जिले के चार थानों में विभागीय कसावट लाने के लिए चार थानेदारों को भी बदल दिया है। सब इंस्पेक्टर प्रेमचंद साहू को दीपका थाने से कटघोरा थाने भेजा गया है। जबकि टीआई धर्मनारायण तिवारी को लाइन से दीपका थानेदार का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह इंस्पेक्टर गणेशराम यादव को करतला थाने का प्रभारी बनाया गया है।जबकि इंस्पेक्टर लोकनायक यादव को लेमरु थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उपनिरीक्षक प्रेमचंद साहू लंबे समय से दीपका थाने में जमे हुए थे। जिन्हें अंतत: अब यहां से स्थानांतरित कर एमबी पटेल के सस्पेंशन के बाद कटघोरा थाने का प्रभार दिया गया है। उच्च अधिकारी लगातार पुलिसिंग में कसावट लाने और आम लोगों के बीच पुलिस की अच्छी छवि निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिले की पुलिसिंग में लगातार कुछ ऐसे विवाद पनप रहे हैं। जिससे खाकी दागदार हो रही है। पिछले कुछ समय में कोरबा जिले में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। चोरी, डकैती, हत्या, चाकूबाजी और मारपीट की वारदातें नियमित अंतरालों पर हुई हैं। हालांकि सभी वारदातों के विरुद्ध पुलिस ने ठोस कार्रवाई भी की है।

दल्हा पहाड़, आस्था का मेला और शौर्य प्रदर्शन

जांजगीर चांपा। दल्हा पहाड़ एक प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र है। यह अकलतरा ब्लॉक में स्थित है। नागपंचमी पर दल्हा पहाड़ चढ़ने की बरसों पुरानी परम्परा है।

दल्हा पहाड़ में हर साल मेला लगता है। इस बार भी नागपंचमी पर मेला लगा, जिसमें बड़ी संख्या में जांजगीर चांपा जिले के साथ ही प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। यहां पहुंच कर श्रद्धालु अर्ध नारीश्वर, नाग नागिन मंदिर,श्री सिद्ध मुनि आश्रम,कृष्ण मंदिर का दर्शन करते हैं और सूर्य कुंड का पवित्र जल पी कर रोग मुक्त होने की कामना करते हैं।सूर्य कुंड के पवित्र जल का विशेष महत्व है। जल खराब नहीं होता। कुंड में पानी की कमी नहीं होती है।बुजुर्गों ने बताया कि दल्हा पहाड़ की चोटी में लगे झंडा को लाने की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। ग्रामीणों द्वारा टोली बना कर उस झंडा को लाने का प्रयास किया जाता है। जो दल झंडा के साथ वापस लौटता है, उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। समय बदलता गया और अब लोग आस्था के साथ-साथ एडवेंचर के लिए भी नाग पंचमी पर दल्हा पहाड़ चढ़ने पहुंचते हैं।हर साल नाग पंचमी को लगने वाले इस मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए।

नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मान लेना होगी जल्दबाजी:डॉ महंत

एमसीबी। डिप्टी सीएम अरुण साव के नक्सलवाद की विचारधारा पर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार किया है।महंत ने साय सरकार के मंत्रियों और उनकी कार्यशैली पर टिप्पणी की।साथ ही साथ कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म मान लेना अभी जल्दबाजी होगी। डॉ चरणदास महंत ने कहा कि सरकार के कुछ मंत्री तथ्यहीन बातें करते हैं।कई बार मंत्री के मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं।डॉ चरणदास महंत ने इस दौरान नक्सलवाद को लेकर भी बात की। इसे केवल बंदूक और हिंसा के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। नक्सलवाद एक विचारधारा और सोच के रूप में भारत में आया था, जिसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त होने में अभी समय लग सकता है। यह निश्चित रूप से खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का प्रभाव लगातार कमजोर हुआ है।हाल के वर्षों में इसका दायरा काफी सिमटा है। मनेंद्रगढ़ दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरण दास महंत ने बंजी में प्रस्तावित पावर प्लांट की मांग को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बंजी में पावर प्लांट की मांग कोई नई मांग नहीं है बल्कि यह काफी पुरानी मांग है। जहां तक उन्हें जानकारी है, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ। रमन सिंह ने भी इस संबंध में वादा किया था महंत ने कहा कि क्षेत्र में कोयला भी निकल रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

असली सोना चांदी बताकर नकली जेवर पकड़ाए

सूरजपुर। पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद भी ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सूरजपुर जिले में नकली सोना-चांदी देकर महिलाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले में रामानुजनगर थाना क्षेत्र के दो से तीन गांवों की करीब आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने थाने पहुंचकर शिकायत की है। नारायणपुर निवासी व्यक्ति सोना-चांदी का व्यवसाय करता है और गांव-गांव जाकर लोगों को आभूषण बेचता है। इसी दौरान कई महिलाओं ने उससे सोने और चांदी के गहने खरीदे थे। महिलाओं के मुताबिक खरीदे गए गहने जब उन्होंने सुनार दुकान में जांच कराई तो वे नकली बताए गए। इसके बाद महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ। महिलाओं ने रामानुजनगर थाने में ठगी की शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कई महिलाओं द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखत हुए तत्परता से जांच शुरू कर दी है। महिलाओं द्वारा दिखाए गए आभूषणों की जांच की जा रही है।

एमबीए कर मोहन चंद्राकर ने खेती को बनाया मॉडल

महासमुंद। जिले के ग्राम केशवा निवासी मोहन चंद्राकर प्रगतिशील एवं नवाचारी किसान के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। एमबीए की शिक्षा के बाद वर्ष 1997 से 2013 तक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले श्री चंद्राकर ने वर्ष 2013 में खेती की ओर लौटकर कृषि को व्यवसाय के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। श्री चंद्राकर जैविक एवं प्राकृतिक पद्धति से खेती करते हुए पारंपरिक, सुगंधित और औषधीय गुणों वाली फसलों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे किसानों को आधुनिक तकनीक, फसल विविधीकरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार से जुड़ाव के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिससे अनेक किसानों की आय में वृद्धि हुई है। श्री चंद्राकर बताते हैं कि वे अपने लगभग 6 एकड़ बंजर भूमि पर 400 ऑस्ट्रेलियन टीक के पौधे लगाए, जो आज 20 से 30 फीट ऊंचे हो चुके हैं। वर्ष 2024 से सफेद चंदन के 200 पौधों सहित आम, महुआ, जामुन, चीकू, अमरूद और अन्य फलदार एवं उपयोगी वृक्षों का भी संरक्षण एवं रोपण कर रहे हैं।

रक्षाबंधन पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान शुरू

गरियाबंद। छत्तीसगढ़, खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के निर्देश पर आगामी रक्षाबंधन त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन अभियान बने खाबो-बने रहिबो 2.0 के तहत जिले में 23 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मिल्क स्वीट्स के नाम से विक्रय की जाने वाली, किंतु वनस्पति तेल अथवा वनस्पति वसा से तैयार मिठाइयों, अवमानक मिठाइयों तथा बिना लेबल के प्लास्टिक डिब्बों में भ्रामक नामों से विक्रय की जाने वाली मिठाइयों की जांच की जाएगी। इनमें काजू कतली, काजू बर्फी, मगज लड्डू, बर्फी, पेड़ा सहित अन्य नाम से लेबल वाले मिठाइयां शामिल हैं। इसके अलावा सभी अस्थायी एवं स्थायी कन्फेक्शनरी तथा नमकीन निर्माता, थोक एवं फुटकर विक्रेता, होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड इकाइयों का भी सघन निरीक्षण किया जाएगा। जिला मुख्यालक के विभिन्न खाद्य कारोबारियों को मिलावटी, अमानक, मिथ्याछाप एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय नहीं करने के निर्देश दिए गए।

अंबिकापुर में 15 छात्राओं का एचपीवी टीकाकरण संपन्न

अम्बिकापुर। एचपीवी संक्रमण एवं इससे होने वाले गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए दशमेश पब्लिक स्कूल, अंबिकापुर में एचपीवी टीकाकरण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। टीकाकरण सत्र के दौरान विद्यालय की 15 पात्र छात्राओं को एचपीवी का टीका लगाया। इस अवसर पर छात्राओं एवं विद्यालय प्रबंधन को एचपीवी टीकाकरण के महत्व, इसकी सुरक्षा एवं लाभों के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। टीकाकरण सत्र को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में डॉ. साधना मिश्रा, स्टाफ नर्स संजिता एक्का, एएनएम शशि सिन्हा, आरएचओ सागर राय एवं अजित मिंज तथा ऑपरेटर अनुप का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभिभावकों एवं आमजन से अपील की है कि निर्धारित आयु वर्ग की सभी पात्र बालिकाओं का समय पर एचपीवी टीकाकरण अवश्य कराएं। उन्होंने कहा कि समय पर टीकाकरण कराकर बालिकाओं को भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव में मदद की जा सकती है।

मुन्नी बाई के घर पहुंचा नल का जल, आसान हुआ जीवन

एमसीबी। कभी स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करना, कुएं और हैंडपंप से पानी भरकर घर तक लाना और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घंटों समय खर्च करना ग्राम रेंद की मुन्नी बाई के जीवन का हिस्सा था। पानी की व्यवस्था में लगने वाला समय और मेहनत उनके दैनिक जीवन को कठिन बना देता था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की सुविधा पहुंचने के बाद मुन्नी बाई के घर में न केवल पानी पहुंचा है, बल्कि उनके जीवन में सुविधा, स्वच्छता और उम्मीद की नई शुरुआत हुई है। इसी पहल का लाभ ग्राम रेंद की निवासी मुन्नी बाई को भी मिला है। मुन्नी बाई बताती हैं कि पहले घर की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। स्वच्छ पानी के लिए उन्हें घर से दूर स्थित कुएं और हैंडपंप तक जाना पड़ता था। पानी भरने के बाद उसे घर तक लाने में काफी समय और श्रम लगता था। गर्मी के दिनों में यह परेशानी और भी बढ़ जाती थी।

बालक आश्रम में छात्र की मलेरिया से मौत

विधायक मंडावी ने स्वास्थ्य विभाग और सरकार पर साधा निशाना

विधायक मंडावी ने साधा

ईधर मामले को लेकर विपक्ष के बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी ने सरकार और संबंधित विभाग पर गंभीर लापरवाही के साथ अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। विधायक ने कहा कि आदिवासी अंचल के बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं

बीजापुर। बीजापुर में जांगला स्थित बालक आश्रम में अध्ययनरत कक्षा पांचवीं के आदिवासी छात्र लश्कर वट्टी की मलेरिया से मौत हो गई। परिजनों और स्थानीय स्तर पर इलाज में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और आश्रमों में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।

विधायक ने बस्तर को मलेरिया मुक्त किए जाने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए इसे झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र में मलेरिया से बच्चों की मौत हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।घटना के बाद आश्रम में रह रहे अन्य बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, मलेरिया की रोकथाम और समय पर उपचार की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जिम्मेदारों की भूमिका की जांच होती है या नहीं।

बाल सुधार गृह में बड़ी घटना

बिलासपुर। बिलासपुर के सरकंडा स्थित बाल सुधार गृह में एक बार फिर गंभीर घटना सामने आई है। दुष्कर्म के मामले में यहां लाए गए 18 वर्षीय शुभम अगरिया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद बाल सुधार गृह की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।जानकारी के अनुसार शुभम अगरिया रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ क्षेत्र के किरमिडांड गांव का रहने वाला था। उसे 15 अगस्त को बिलासपुर स्थित बाल सुधार गृह लाया गया था। इसके कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत की खबर सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ आवश्यक कार्रवाई की और मृतक के परिजनों को भी सूचना दी गई। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। बाल सुधार गृह में इससे पहले भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। यहां चार बंदियों द्वारा एक कर्मचारी की हत्या कर फरार होने की घटना सामने आई थी। बाद में पुलिस ने चारों को पकड़ लिया था।

कोरिया के जीराफूल चावल ने बनाई नई पहचान

कोरिया। जिले का पारंपरिक और सुगंधित जीराफूल चावल प्राकृतिक खेती और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के प्रभावी मॉडल से नई पहचान बना रहा है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा स्थानीय कृषि उत्पादों को प्रोत्साहित करने और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जीराफूल चावल की पहुंच स्थानीय बाजार से आगे व्यापक स्तर तक बढ़ रही है। कृषि विभाग के उप संचालक राजेश भारती ने बताया कि कलेक्टर रोक्तिमा यादव के मार्गदर्शन में कोरिया जिले में एफपीओ से जुड़े 832 किसान प्राकृतिक खेती पद्धति से जीराफूल धान का उत्पादन कर रहे हैं। किसान खेती में जीवामृत, बीजामृत जैसे जैव- आधारित इनपुट का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती से उत्पादित जीराफूल धान को गुणवत्ता, प्रमाणन और बेहतर पैकेजिंग के माध्यम से बाजार में विशिष्ट पहचान दिलाने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों की उपज को केवल उत्पादन तक सीमित रखने के बजाय उसे संगठित बाजार से जोड़ने में एफपीओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सोनहत गौरव एग्रोफेड कृषक उत्पादक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित के माध्यम से जीराफूल चावल के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एवं विपणन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों को सामूहिक रूप से बाजार तक पहुंच बनाने और अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर मिल रहे हैं।

जीराफूल चावल की प्राकृतिक खेती, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, प्रमाणन, आकर्षक पैकेजिंग और एफपीओ के माध्यम से विपणन ने 'उत्पादन से मूल्य संवर्धन और बाजार तक' की पूरी श्रृंखला तैयार की है। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से कोरिया के जीराफूल धान की प्राकृतिक खेती और एफपीओ मॉडल से जुड़े प्रयासों को सराहा गया है।

संक्षिप्त समाचार

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राज ने यूसीसी समिति सदस्यों से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समिति के सदस्यों से सौजन्य मुलाकात की। इस विशेष भेंट के दौरान डॉ. सलीम राज ने आम नागरिकों की सहूलियत और बेहतर समझ के लिए यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर सरल भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित करने के विचार से समिति को अवगत कराया, ताकि राज्य का हर नागरिक इसके प्रावधानों को आसानी से समझ सके। यूसीसी समिति के प्रमुख सदस्यों ने राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से यूसीसी के ड्राफ्ट हेतु अपने सुझाव साझा करने का विशेष आग्रह किया है। राज्य में यूसीसी समिति ने अपनी कार्यप्रणाली पूरी सक्रियता से प्रारंभ कर दी है। राज्य के आम नागरिक समान नागरिक संहिता को लेकर अपने विचार या सुझाव देना चाहते हैं, तो निम्नलिखित आधिकारिक पतों एवं माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। ई-मेल के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव सीधे इस ucc-chhattisgarh@cg.gov.in पर भेज सकते हैं। इसी तरह वेब पोर्टल के माध्यम से समिति के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन https://ucc.cgstate.gov.in/ सुझाव दर्ज करा सकते है।

संभाग स्तरीय रेड रिबन प्रश्नोतरी स्पर्धा में 30 विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने लिया भाग

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण

समिति, रेड रिबन क्लब एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में गुरुकुल महिला महाविद्यालय में एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। जिसमें रायपुर जिले के 30 विद्यालयों से कक्षा 9वीं एवं 11वीं के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। जिसमें प्रथम स्थान - प्रिंसी यादव, आयुष अग्रवाल एन एच गोयल वर्ल्ड स्कूल, द्वितीय स्थान - भूमिका साहू, ऐश्वर्य कुमार दुबे, ग्लोरियस हाइयर सेकेंडरी स्कूल व तृतीय स्थान - अदिति चौधरी,यीशु देवांगन, सेजस स्कूल,बिरगांव रही। प्रतियोगिता के विजेताओं को निर्णायक मंडल एवं अतिथियों द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य युवाओं में एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सजगता विकसित करना तथा जिम्मेदार नागरिकता की भावना को प्रोत्साहित करना था।

मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के लिए 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और कलाकारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना-2026 के अंतर्गत प्रदेश के लोक कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। योजना का उद्देश्य पारंपरिक लोक कलाओं को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना, कलाकारों का सम्मान बढ़ाना तथा कला दलों के सतत विकास को नई गति प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ी पाक कला (पारंपरिक व्यंजन) तथा छत्तीसगढ़ी सौंदर्यकला (श्रृंगार) से जुड़े कलाकार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय, नया रायपुर स्थित कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। योजना के तहत पात्र कलाकारों का चिन्हारी पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य होगा। चयनित कलाकारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 12 हजार रुपये से अधिकतम 24 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि ई-पेमेंट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी।

छत्तीसगढ़ में औसतन 731.3 मिमी वर्षा दर्ज

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन के दौरान बारिश का दौर जारी है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में अब तक औसतन 731.3 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कि पिछले 10 वर्षों के औसत (739.2 मिमी) का 98.9 प्रतिशत है। वहीं, अकेले आज पूरे प्रदेश में औसतन 21.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है। राज्य के विभिन्न संभागों और जिलों में वर्षा की स्थिति में काफी भिन्नता देखी जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिला बारिश के मामले में सबसे आगे चल रहा है, जबकि कांकेर और सुकमा जैसे जिलों में बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफी पीछे है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के सरगुजा जिले में अब तक 425.7 मिमी वर्षा (सामान्य का 75.4%) हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा

वरिष्ठ अधिकारियों को दिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक निर्देश

रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर में आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली । बैठक में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता, साफ-सफाई की व्यवस्था तथा मरीजों को दी जा रही अन्य सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। अधिकारियों से जिलेवार जानकारी लेते हुए यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जरूरी दवाएं और चिकित्सा सुविधाएं समय पर पहुंचें, जिससे आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक मे सेवाओं को और अधिक बेहतर एवं जनोन्मुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

अस्पतालों में स्वच्छता व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त रखने, आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार मिले, इसके लिए कार्ययोजना के अनुसार अमल करने को कहा गया। इसके साथ ही चिकित्सा उपकरणों के रखरखाव, स्टाफ की उपस्थिति और मरीजों के साथ संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी।

भाजपा में कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता : जायसवाल

रायपुर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं को नजरअंदाज करने वाले कांग्रेस के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस की तरह नहीं है। भाजपा में कोई पद बड़ा या छोटा नहीं होता है। कांग्रेस हर वक्त उपेक्षा करने में लगी रहती है, इसलिए उन्हें हर जगह यही नजर आता है।

मंत्री जायसवाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार जताते हुए कहा कि सासंद रूप कुमारी चौधरी को राष्ट्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष और दीपक म्हस्के को सोशल मीडिया का प्रभारी बनाकर उन्होंने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। रायपुर जिले के नकटी गांव में बीते दिनों हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अब वह विधायक अनुज शर्मा और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बंगले के घेराव की तैयारी में है। इसे लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव करना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के धान खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोपों पर मंत्री जायसवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कांग्रेस अपने कार्यकाल के भ्रष्टाचार की समिति बना लेती। वह अपने भ्रष्टाचार की जांच करा लें। भाजपा कार्यकाल में समय पर धान का उठाव किया जा चुका है।

ट्रैक मरम्मत कार्य के कारण यातायात रहेगा बंद

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल अंतर्गत बालोद-कुसुमकसा स्टेशनों के मध्य स्थित समपार फाटक क्रमांक ।। -50, कि.मी. 929/13-14 (बालोद गेट- पाररास फाटक) पर रेलवे ट्रैक के आंशिक एवं पूर्ण मरम्मत कार्य के कारण सड़क यातायात निर्धारित अवधि में बंद रहेगा। 24 अगस्त सोमवार, रात्रि 08 बजे से 25 अगस्त 2026, मंगलवार, प्रात: 08 बजे तक। 25 अगस्त मंगलवार, रात्रि 10 बजे से 26 अगस्त 2026, बुधवार, प्रात: 7 बजे तक। 26 अगस्त बुधवार, रात्रि 10 बजे से 27 अगस्त 2026, गुरुवार, प्रात: 8 बजे तक। उक्त अवधि के दौरान समपार फाटक क्रमांक डीडी-50 से सड़क वाहनों का आवागमन पूर्णत: बंद रहेगा। रेल प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि उक्त अवधि में इस समपार फाटक से आवागमन न करें।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से मजबूत हो रही समाज कल्याण विभाग की प्रशासनिक कार्यदक्षता

रायपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशासनिक और वित्तीय दक्षता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यस्तरीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 2026-27 आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र, माना कैंप, रायपुर में प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर प्रतिभागियों को शासकीय कार्यों के सुचारू एवं नियमानुसार संपादन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता विषय पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। सेवानिवृत्त वित्त नियंत्रक, छत्तीसगढ़ वित्त शासन, श्रीमती तृप्ति शर्मा ने प्रतिभागियों को वित्तीय नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देते हुए शासकीय कार्यों में वित्तीय प्रावधानों के उचित अनुपालन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया।

द्वितीय सत्र में कार्यालयीन व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर प्रशिक्षण हुआ। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव श्री बी. एस. राजपूत ने सर्विस बुक के संधारण, नस्तियों के निर्माण एवं रख-रखाव, शासकीय पत्राचार, नोटिंग-ड्राफ्टिंग तथा आवक-जावक प्रक्रिया सहित विभिन्न कार्यालयीन विषयों पर प्रतिभागियों को व्यावहारिक जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन, दस्तावेजों के व्यवस्थित संधारण तथा कार्यालयीन कार्यों में दक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। राज्यस्तरीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभागीय अमले की प्रशासनिक क्षमता, वित्तीय समझ और कार्यालयीन दक्षता को सुदृढ़ करना है।

मुआवजा, पुनर्वास के बाद ही मानिकपुर खदान की जनसुनवाई

रायपुर। मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना की प्रस्तावित जनसुनवाई को लेकर उद्योग मंत्री एवं कोरबा नगर विधायक लखन लाल देवांगन ने प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हित में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसईसीएल कोरबा के महाप्रबंधक से चर्चा कर स्पष्ट निर्देश दिया कि मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से जुड़े लंबित कार्यों का यथोचित निराकरण तथा काचांदी नाला डायवर्सन की प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही जनसुनवाई आयोजित की जाए।

मानिकपुर ओपन कास्ट एक्सपेंशन परियोजना के तहत कोयला उत्पादन क्षमता को 5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए किए जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 21 अगस्त 2026 को जनसुनवाई प्रस्तावित थी। मंत्री देवांगन ने प्रभावित लोगों की भावनाओं और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए एसईसीएल अधिकारियों से अब तक की गई कार्रवाई और लंबित प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी ली।

बताया गया कि परियोजना से प्रभावित भिलाईखुर्द ग्राम में मार्च 2026 में किए गए सर्वे से संबंधित मुआवजा प्रकरणों के साथ पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना से जुड़े कार्य अंतिम चरण में हैं। इन प्रकरणों का अभी निराकरण किया जाना बाकी है।

इसी तरह कुदरी ग्राम के पास काचांदी नाला डायवर्सन का मामला भी महत्वपूर्ण है। जल संसाधन विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाना है और नाला डायवर्सन के संबंध में प्रारंभिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हितों से जुड़े सभी मामलों का समाधान किए बिना जनसुनवाई कराना उचित नहीं होगा।

राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई आयोजित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने तथा विभिन्न विभागों और संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राज्य स्तरीय टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई। एक्सरसाइज के दौरान बाढ़ प्रबंधन नीतियों, एवं बाढ़ के दौरान प्रभावितों को त्वरित सहायता पहुंचाना, मौसम विज्ञान और जल संसाधन विभाग का आवश्यक समन्वय, बाढ़ की स्थिति में निगरानी, चेतावनी एवं सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से डाऊन स्ट्रीन के गांवों को पहले से सचेत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी तरह से बाढ़ आपदा के समय एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर सेना एवं अन्य बचाव दलों में आपसी समन्वय पर चर्चा हुई। बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत कैंप की व्यवस्था एवं प्रभावितों के लिए जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए मेडिकल टीम की तैयारियों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी साझा की गई।

बैठक में सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा कि आपदा की स्थिति में फील्ड स्तर पर कार्य करने वाले सभी कर्मियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारियों की स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है।

रायपुर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पुलिस द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर। छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम मुक्त बनाने के संकल्प के साथ, आज रायपुर स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पुलिस अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं और इंटर्न्स के लिए एक विशेष साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे देश के सबसे अनोखे और इनोवेटिव साइबर जागृति अभियान के तहत आयोजित किया गया।

प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम के विरुद्ध सुरक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा 15 अगस्त से 02 अक्टूबर 2026 तक पूरे प्रदेश में 07 सप्ताह का साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के तय कार्यक्रम के अनुसार, पहले सप्ताह में डिजिटल सतर्कता और बुनियादी सुरक्षा के लिए स्कूल और कॉलेजों में अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दंत चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रों और इंटर्न्स को पुलिस अधिकारियों द्वारा साइबर अपराधों के नए तरीकों, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और बुनियादी साइबर सुरक्षा के विषय में जागरूक किया गया।

कार्यक्रम के दौरान युवाओं को इस अभियान की मुख्य थीम साइबर जागृति की एक सेल्फी से जोड़ा गया।

छात्रों और इंटर्न्स को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी लिंक को क्लिक कर या QR Code को स्कैन करके, जागरूकता संदेश वाली सेल्फी फ्रेम में अपनी सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उपस्थित युवाओं ने अपनी सेल्फी को स्वयं के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट भी किया, ताकि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का संदेश उनके फॉलोअर्स और फ्रेंड्स तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

यह प्रक्रिया इस महाभियान का मुख्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनभागीदारी से साइबर क्राइम के विरुद्ध जागरूकता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक तेजी से पहुंचाना है।

दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस व्यापक अभियान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा जी द्वारा किया गया है। राज्य पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि जिस तरह देश की आज़ादी के लिए करोड़ों देशवासी एकजुट होकर लड़े थे, उसी तरह साइबर जागृति अभियान के लिए साथ मिलकर प्रदेश को साइबर सुरक्षित बनाना होगा। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के सभी छात्रों और इंटर्न्स ने पुलिस का सहयोग करते हुए छत्तीसगढ़ को साइबर क्राइम मुक्त बनाने का संकल्प लिया।

भाजपा राष्ट्रीय मीडिया विभाग की नई टीम

राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रचार-प्रसार व संवाद तंत्र को नए आयाम देगी : पाण्डेय

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मीडिया विभाग के राष्ट्रीय संयोजक एवं सह संयोजकों की नियुक्ति पर भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ दी हैं।

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद श्री पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में संगठन निरंतर सुदृढ़ और गतिशील हो रहा है। श्री पाण्डेय ने वरिष्ठ सांसद अनिल बलूनी (उत्तराखंड) को राष्ट्रीय मीडिया संयोजक तथा आशीष उषा अग्रवाल (मध्य प्रदेश), प्रदीप भण्डारी (दिल्ली) एवं सिद्धार्थ यादव (दिल्ली) को राष्ट्रीय मीडिया सह संयोजक नियुक्ति पर कहा कि श्री बलूनी के दीर्घकालिक सांगठनिक एवं मीडिया प्रबंधन अनुभव तथा युवा व प्रखर सह-संयोजकों की ऊर्जा से भाजपा मीडिया विभाग केंद्र व राज्य सरकारों की जनहितैषी नीतियों, विकास कार्यों और संगठन की विचारधारा को जन-जन तक और अधिक मजबूती व प्रखरता से पहुँचाने में सफल होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई टीम राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रचार-प्रसार व संवाद तंत्र को नए आयाम देगी। भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक हेमन्त पाणिग्राही ने छत्तीसगढ़ भाजपा मीडिया परिवार की ओर से सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों के सफल और ऊर्जावान कार्यकाल की मंगलकामना की।

दीपक बैज ने शिक्षा से कानून-व्यवस्था तक उठाए सवाल, भाजपा प्रभारी की नियुक्ति पर कसा तंज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को राज्य की भाजपा सरकार पर शिक्षा, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य और धान खरीदी समेत कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। बैज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाएं लगातार बदहाल होती जा रही हैं और सरकार जनता की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय दिखावे की राजनीति में व्यस्त है।

दीपक बैज ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कई स्कूल ऐसे हैं, जहां बच्चों के लिए स्कूल भवन तक उपलब्ध नहीं है। कई स्कूलों के भवन जर्जर हालत में हैं और बारिश के दौरान उनकी छतों से पानी टपक रहा है।

उन्होंने कहा कि धमतरी में शिक्षकों की कमी से परेशान होकर बच्चों ने स्कूल में ताला लगा दिया। धमधा में स्कूल भवन नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए बैज ने कहा कि यह शिक्षा मंत्री का ही जिला है, इसके बावजूद वहां की स्थिति चिंताजनक है।

बस्तर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहां दो साल से स्कूल भवन का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और बच्चे पंचायत भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। बैज ने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों तक अब तक न किताबें पहुंची हैं और न ही ड्रेस। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री को रील बनाने से फुर्सत नहीं है और सरकार ने प्रदेश के स्कूली सिस्टम को बर्बाद कर दिया है।

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी पीसीसी चीफ ने सरकार को घेरा। उन्होंने इसे असहनीय बताते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में महिलाओं की हत्या और दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बैज ने आरोप लगाया कि एक ही दिन में एक महिला के साथ दो बार गैंगरेप जैसी गंभीर घटना होना प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू कमिश्नरी व्यवस्था भी फेल हो चुकी है। बैज ने गृहमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें फोटो सेशन से फुर्सत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ अब उत्तर प्रदेश और बिहार को भी पीछे छोड़ रहा है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के मामले में दीपक बैज ने भाजपा नेता अजय चंद्राकर से इस मामले की असलियत बताने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। बैज ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक नहीं, 10 एफआईआर भी दर्ज कर दी जाएं, लेकिन दबाव की राजनीति बंद होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को पहले अपने जिले की व्यवस्था संभालनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर में लोग मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों से जान गंवा रहे हैं।

बैज ने दवाओं की खरीदी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से दवाओं की खरीदी की जा रही है और अमानक तथा नकली दवाएं खरीदे जाने का मामला सामने आ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से इसके लिए जनता से माफी मांगने की मांग की। धान खरीदी को लेकर दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की टीम प्रदेश के धान खरीदी और संग्रहण केंद्रों का निरीक्षण करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई जगह धान खुले में पड़ा हुआ है और धान को जानबूझकर भिगोया जा रहा है।

बैज ने कहा कि धान की खरीदी से लेकर उसके उठाव तक भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस की टीम मौके पर जाकर पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के माध्यम से कथित भ्रष्टाचार को सामने लाएगी।

खुले नाले में बच्चे की मौत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बैज ने कहा कि खुली नाली को ढंकना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार जनता को सुरक्षित नहीं रख सकती तो उसे सत्ता की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। भाजपा में प्रदेश प्रभारी की नियुक्ति को लेकर भी बैज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन-चार महीने से भाजपा का प्रदेश प्रभारी नहीं है। उनके मुताबिक बिना प्रदेश प्रभारी के भाजपा विकलांग हो चुकी है और बिना सिर-पैर के काम कर रही है। पीसीसी चीफ के इन बयानों के जरिए कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश सरकार को घेरते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था और धान खरीदी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल डेका से की भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्यपाल को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। राज्यपाल श्री डेका ने भी मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की सुख-समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की।इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि का चेक राज्यपाल रमेन डेका को सौंपा।

सोशल मीडिया कार्यों के लिए पियूष अग्रवाल सम्मानित

रायपुर।स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा आयोजित समारोह में जनसंपर्क एवं सोशल मीडिया प्रबंधन में

उत्कृष्ट कार्य के लिए पियूष अग्रवाल को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। महापौर मीनल चौबे द्वारा पियूष अग्रवाल को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर निगमायुक्त संभित मिश्रा, सभापति सूर्यकांत राठौर, नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। पियूष अग्रवाल द्वारा नगर निगम की योजनाओं, विकास कार्यों, जनहितकारी अभियानों एवं निगम की विभिन्न गतिविधियों को सोशल मीडिया एवं जनसंपर्क माध्यमों के जरिए प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान दिया जा रहा है। प्रशस्ति-पत्र में उनके द्वारा शासकीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन में दिए गए सराहनीय योगदान की प्रशंसा की गई। सम्मान प्राप्त करने पर पियूष अग्रवाल ने नगर निगम प्रशासन एवं महापौर के प्रति आभार व्यक्त किया।

रायपुर एयरपोर्ट पर उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस आयोजित

रायपुर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, रायपुर में 80वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास, उत्साह एवं देशभक्ति की भावना के साथ

मनाया गया। समारोह में एयरपोर्ट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए एयरपोर्ट निदेशक ने रायपुर एयरपोर्ट की हाल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के ASQ सर्वेक्षण में रायपुर एयरपोर्ट ने देशभर में द्वितीय स्थान प्राप्त कर यात्री सेवा एवं ग्राहक संतुष्टि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरपोर्ट के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ एयरलाइंस, CISF, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, हितधारकों एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सफलता सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। एयरपोर्ट निदेशक ने रायपुर एयरपोर्ट के भविष्य के विकास एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।

मंडल रेल प्रबंधक ने किया ध्वजारोहण

रायपुर। पूरे राष्ट्र के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों में पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडल का

मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, रायपुर के प्रांगण में आयोजित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अध्यक्षा, सेक्रो श्रीमती शिखा सिंह की गरिमामयी उपस्थिति रही।कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम् राष्ट्रगीत के साथ हुआ। इसके पश्चात मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद ने प्रात: 9:00 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान की सुमधुर धुन के बीच राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। पुन: राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर मंडल रेल सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस तथा स्काउट एवं गाइड के सदस्यों द्वारा

तेंदूपत्ता सहित वनोपज के बेहतर विपणन पर सरकार का जोर: वन मंत्री कश्यप

रायपुर। वन मंत्री श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति(आईडीसी) की 321वीं बैठक आयोजित हुई। यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्री श्री कश्यप के निवास/कार्यालय में आयोजित थी। बैठक में वर्ष 2026 में संग्रहित एवं गोदामीकृत तेंदूपत्तों के विक्रय के लिए द्वितीय चरण की कार्यवाही तथा वर्ष 2025 सीजन के क्रेता करारनामा समाप्त तेंदूपत्ता लॉट के विक्रय के लिए प्राप्त निविदाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुवा, वन बल प्रमुख श्री अरूण कुमार पाण्डेय, सचिव श्री अमरनाथ, मुख्य वन संरक्षक श्री कोशलेन्द्र कुमार, मुख्य वनसंरक्षक श्रीमती संजीता गुप्ता, कार्यकारी निदेशक वन श्री एस.वेंकटचलम् सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में 4 अगस्त 2026 को आमंत्रित निविदाओं में प्राप्त दरों के अनुमोदन से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वनोपज के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी प्रक्रिया और संग्रहणकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए तेंदूपत्ता सहित अन्य वनोपज के प्रभावी विपणन पर जोर दिया।

संग्राहकों के हितों को प्राथमिकता

राज्य सरकार द्वारा वन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों और आदिवासी परिवारों की आजीविका को मजबूत करने के लिए लघु वनोपज के संग्रहण और विपणन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिले, इसके लिए शासन द्वारा संग्रहण मूल्य, विपणन व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। बैठक में तेंदूपत्ते के भंडारण, लॉटवार विक्रय और प्राप्त निविदा दरों सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि संग्रहित वनोपज का समयबद्ध और बेहतर तरीके से विक्रय किया जा सके।

वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था को मिल रहा बढ़ावा: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार वनवासियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को प्राथमिकता दे रही है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में वनोपज के संग्रहण से लेकर प्रसंस्करण और विपणन तक की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। इससे वनांचल के लोगों को रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल रहा है।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने यूसीसी समिति सदस्यों से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समिति के सदस्यों से सौजन्य मुलाकात की। इस विशेष भेंट के दौरान डॉ. सलीम राज ने आम नागरिकों की सहूलियत और बेहतर समझ के लिए यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर सरल भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित करने के विचार से समिति को अवगत कराया, ताकि राज्य का हर नागरिक इसके प्रावधानों को आसानी से समझ सके।यूसीसी समिति के प्रमुख सदस्यों ने राज्य के प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संगठनों और आम जनता से यूसीसी के ड्राफ्ट हेतु अपने सुझाव साझा करने का विशेष आग्रह किया है।राज्य में यूसीसी समिति ने अपनी कार्यप्रणाली पूरी सक्रियता से प्रारंभ कर दी है। राज्य के आम नागरिक समान नागरिक संहिता को लेकर अपने विचार या सुझाव देना चाहते हैं, तो निम्नलिखित आधिकारिक पतों एवं माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। ई-मेल के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव सीधे इस ucc-chhattisgarh@cg.gov.in

पर भेज सकते हैं। इसी तरह वेब पोर्टल के माध्यम से समिति के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइनhttps://ucc.cgstate.gov.in/ सुझाव दर्ज करा सकते है। राज्य के नागरिक डाक / पत्राचार द्वारा अपने लिखित सुझाव कार्यालय, समान नागरिक संहिता समिति कमरा नंबर - 202, न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइन्स,रायपुर, छत्तीसगढ़- 492001 के पते पर स्पीड पोस्ट या साधारण डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर लिखित आवेदन/ज्ञापन व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

नवा रायपुर में करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्थापित करने की दिशा में पहल

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी से आज रायपुर स्थित उनके निवास पर भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर कार्यालय के महाप्रबंधक श्री मनीष पराशर ने शिष्टाचार भेंट की। प्रभारी अधिकारी का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात हुई इस मुलाकात में छत्तीसगढ़ में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के विस्तार, मुद्रा प्रबंधन तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से संबंधित विभिन्न विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान वर्तमान में नागपुर से होने वाले करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को नवा रायपुर में स्थापित करने की दिशा में की जा रही महत्वपूर्ण पहल पर भी चर्चा हुई। नवा रायपुर में करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था विकसित होने से राज्य में मुद्रा प्रबंधन और बैंकिंग सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने में मदद मिलेगी।श्री पराशर ने वित्त मंत्री को राज्य में बैंकिंग सेवाओं तथा मुद्रा प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक, रायपुर कार्यालय में हाल ही में प्रारंभ की गई सॉइल्ड नोट्स के स्थानीय प्रसंस्करण की व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी साझा की गई। इस सुविधा से प्रचलन से वापस प्राप्त अनुपयोगी एवं खराब हो चुके नोटों का प्रसंस्करण अब स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा।मुलाकात के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रस्तावित नवीन आवासीय परियोजना तथा इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने इन पहलों की जानकारी प्राप्त करते हुए राज्य शासन की बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी अपेक्षाओं को साझा किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक एवं राज्य शासन के बीच निरंतर सहयोग और बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।

स्वतंत्रता दिवस पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का संदेश

आजादी की विरासत बचाना हर भारतीय का कर्तव्य छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को बताया विफल

रायपुर। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरोहर है, इसे सम्हाल कर रखना हर भारतीय का पहला कर्तव्य है।

उन्होंने अपने संदेश में कांग्रेस के योगदान को याद करते हुए कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में रियासतों को एक कर, लोकतांत्रिक भारत की मजबूत नींव रखी गई। साथ ही उन्होंने वर्तमान केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर लोकतंत्र, युवाओं और आम जनता के मुद्दों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।दीपक बैज ने कहा कि तिरंगा फहराते समय हमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वीरनारायण सिंह जैसे शहीदों और महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष बोस, सरदार पटेल, बाबा साहेब अंबेडकर जैसे नेताओं का स्मरण होता है। बस्तर के भूकाल आंदोलन के नायक गुंडाधुर, ढेबरीधूर और झाड़ा सिरहा ने भी आजादी की नई राह दिखाई।उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश के सामने चुनौती थी उसे स्वाबलंबी और प्रजातांत्रिक बनाना।

वंदे मातरम की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर छायाचित्र प्रदर्शनी

रायपुर। राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित सात दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी के चौथे दिन विद्यार्थियों और आम नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। स्वतंत्रता संग्राम, छत्तीसगढ़ के वीर सेनानियों एवं जनजातीय नायकों के संघर्ष, 'वंदे मातरम' की 150 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और राज्य की विकास यात्रा को तस्वीरों के माध्यम से जानने के साथ ही विद्यार्थियों ने ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मंच पर आकर सवालों के जवाब देने की गतिविधि ने विद्यार्थियों के ज्ञान के साथ उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया।

प्रदर्शनी में आयोजित प्रश्नोत्तरी की खास बात यह रही कि इसे केवल सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि विद्यार्थियों को खेल-खेल में छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जनजातीय नायकों के जीवन, संघर्ष

और योगदान से परिचित कराया गया। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने किताबों में स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा है, लेकिन इस तरह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने प्रदेश के नायकों के बारे में जानना उनके लिए नया और बेहद रोचक अनुभव रहा।

प्रदर्शनी में कंप्यूटर के माध्यम से विशेष रूप से तैयार की गई प्रश्नोत्तरी विद्यार्थियों के लिए खास आकर्षण बनी रही। इसमें तीन टीमों को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पहचानने की चुनौती दी गई। विद्यार्थियों को संबंधित सेनानी के नाम का एक क्लू दिया जाता था और इसके बाद टीमों को बारी-बारी से एक-एक अक्षर बताने का अवसर दिया जाता था। जैसे-जैसे सही अक्षर सामने आते जाते, नाम पूरा होने लगता था।

जो टीम सबसे अधिक सही अक्षर बताकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम सबसे पहले पहचान लेती, उसे विजेता घोषित किया जाता। इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थियों में उत्सुकता, प्रतिस्पर्धा और सीखने की ललक साफ दिखाई दी। सही उत्तर मिलने पर विद्यार्थियों और दर्शकों ने तालियों के साथ प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

प्रदर्शनी परिसर में आयोजित छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच-बीच में उद्घोषक द्वारा छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, परंपरा, स्वतंत्रता संग्राम और पर्यटन से जुड़े सवाल पूछे गए। सही जवाब देने वाले प्रतिभागियों का दर्शकों ने तालियों से उत्साहवर्धन किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच इस तरह की प्रश्नोत्तरी ने पूरे वातावरण को जीवंत बना दिया। एक ओर मंच पर छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और लोक कला की मनोहारी प्रस्तुतियां हो रही थीं, वहीं दूसरी ओर दर्शक और विद्यार्थी सवालों के जवाब देकर अपने ज्ञान को परख रहे थे। इस अभिनव संयोजन ने प्रदर्शनी में आने वाले लोगों के अनुभव को और अधिक रोचक एवं ज्ञानवर्धक बना दिया।

संभागायुक्त धावड़े ने किया ध्वजारोहण

रायपुर। संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर श्याम धावड़े ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने अधिकारी-कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। संभागायुक्त ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आजादी के इस पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से स्वाधीनता बहुत संघर्षों और बलिदानों के बाद मिली है। आजादी किसी देश के मूलभूत विकास के लिए सबसे जरूरी है। अपना देश-अपने लोग-अपनी सरकार और अपने निर्णय ही आजादी के मूलभूत मायने हैं। संभागायुक्त ने कहा कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहूति देकर देश को आजाद करा कर विकास के जिस सपने कों संजोया था, उसे पूरा करना हम सब भारतवासियों की जिम्मेदारी है। इस मौके पर श्री धावड़े सभी अधिकारी-कर्मचारियों को अपने-अपने शासकीय दायित्वों का पूरी क्षमता से निर्वहन करने और जनहित के सभी कामों को समय पर पूरा करने की समझाईश भी दी। इस अवसर पर उपायुक्त श्रीमती ज्योति सिंह एवं श्री दिलीप कुमार अग्रवाल सहित कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

विकास योजनाओं को मिले गति, निर्माण कार्य समय-सीमा में हों पूर्ण : तोखन

रायपुर। सांसद लोकसभा क्षेत्र बिलासपुर एवं केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं तथा विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए श्री साहू ने स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए स्थानीय संसाधनों एवं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी

कार्ययोजना तैयार की जाए।

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा हितग्राहियों को आवास निर्माण में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी तरह व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों के लंबित कार्यों को भी प्राथमिकता से पूरा करने कहा। पीएम जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाए जा रहे संपर्क मार्गों की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभागीय समन्वय से निर्माण में आ रही बाधाओं का शीघ्र निराकरण करने और सड़कों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

श्री साहू ने जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले की विशिष्ट पहचान विष्णुभोग धान-चावल की उत्पादकता बढ़ाने, प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने तथा बेहतर विपणन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास करने कहा, ताकि किसानों को स्थानीय उत्पाद का अधिक लाभ मिल सके।

स्वच्छता की समीक्षा के दौरान उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में नियमित कचरा संग्रहण और स्वच्छता व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण से संबंधित वास्तविक एवं अद्यतन जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने पर भी विशेष जोर दिया।

जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए जल निकायों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। श्री साहू ने पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए सघन टीकाकरण अभियान चलाने, कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए प्रभावी प्रयास करने तथा टीबी उन्मूलन और मलेरिया नियंत्रण के लिए विभागीय स्तर पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने जिले में शत-प्रतिशत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने पर भी विशेष जोर दिया।केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री साहू ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त अधिकांश प्रकरण राजस्व विभाग से संबंधित हैं। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया कि नक्शा-बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, त्रुटि सुधार सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए उन्होंने उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न की निर्बाध और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने कहा।

स्वतंत्रता दिवस पर हितग्राहियों को बड़ी सौगात, दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आवंटियों को विलंब अवधि की ब्याज राशि और बकाया जल प्रभार के सरचार्ज पर 50 प्रतिशत की विशेष छूट एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दी गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित थी।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने अपने हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है। मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बकायादार हितग्राहियों को दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की।

यह छूट मंडल की समस्त योजनाओं में निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी।

हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 एवं OTS-2 में आबंटित संपत्तियां इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगी। पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज अर्थात विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि मंडल द्वारा पूर्व में भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ 31 मार्च 2026 तक दिया गया था। इस योजना को हितग्राहियों से अच्छा प्रतिसाद मिला। मंडल की निधि में तरलता बनाए रखने तथा हितग्राहियों को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से पुन: यह योजना लागू की गई है।अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि कई हितग्राहियों द्वारा जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) समय पर जमा नहीं किए जाने के कारण लंबित राशि पर सरचार्ज भारित हो रहा था। हितग्राहियों द्वारा लगातार सरचार्ज में छूट देने का अनुरोध किया जा रहा था।

भाजपा की नई सूची ने जो सियासी संकेत दिया है वह सबके समझ में नहीं आएगी

नीरज कुमार दुबे

नितिन नबीन की बहुप्रतीक्षित टीम का आज आखिरकार ऐलान हो ही गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने संगठन में लंबे समय से चल रही कवायद को अंजाम देते हुए अपनी नई राष्ट्रीय टीम सामने रख दी है। इस टीम में अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण और चुनावी जरूरतों का ऐसा मिश्रण तैयार किया गया है, जिसमें पार्टी के पुराने दिग्गजों से लेकर नए चेहरों तक को जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस पूरी कवायद में दो फैसले राजनीतिक चर्चा के केंद्र में हैं। एक तो अमित मालवीय को आईटी सेल प्रमुख की जिम्मेदारी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर भाजपा के शीर्ष संगठन में वापसी हुई है।

हम आपको बता दें कि आईटी और सोशल मीडिया सेल की कमान अब छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को दी गई है। वहीं अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी की अपनी जिम्मेदारी पर कायम हैं। यानी भाजपा ने डिजिटल मोर्चे पर चेहरे में बदलाव किया है, लेकिन मीडिया प्रबंधन के मौजूदा ढांचे में निरंतरता बनाए रखी है। इस बदलाव को केवल संगठनात्मक फेरबदल मानना मुश्किल है। यह संकेत है कि नितिन नबीन डिजिटल और राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई में नई रणनीति और नए चेहरों के साथ उतरना चाहते हैं। साथ ही चूंकि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं ऐसे में वह जानते हैं कि उस राज्य के किस नेता की कार्यक्षमता का उपयोग कहां पर करना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

इसके अलावा, स्मृति ईरानी की वापसी इस टीम का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। उन्हें उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। आक्रामक राजनीतिक शैली, संसदीय अनुभव और विपक्ष के खिलाफ मुखर राजनीतिक लड़ाई के लिए पहचाने जाने वाली स्मृति ईरानी को संगठन के शीर्ष स्तर पर लाना बताता है कि भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे निर्णायक राज्य में राजनीतिक सक्रियता को और धार देना चाहती है।

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत पांडा, डी. पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, वर्षाबेन नरेंद्रभाई दोशी, डॉ. भारती प्रवीण

पवार, मनप्रीत सिंह बादल, लाल सिंह आर्य, एम. नागराजा, प्रो. तारिक मंसूर और डॉ. मधुचंद्र कर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। छह महिला उपाध्यक्षों की मौजूदगी से महिला प्रतिनिधित्व का संदेश भी स्पष्ट है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय महासचिवों की टीम में विनोद तावड़े, सुनील बंसल, बिप्लब कुमार देब, स्मृति ईरानी, डॉ. सतीश पूनिया, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी और संजय भाटिया शामिल हैं। संगठन के स्तर पर बीएल संतोष राष्ट्रीय महासचिव संगठन बने हुए हैं, जबकि शिवप्रकाश और सौदान सिंह को राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठन की जिम्मेदारी मिली है। इसका अर्थ है कि नबीन ने संगठन की अनुभवी मशीनरी को बनाए रखते हुए राजनीतिक मोर्चे पर अपनी टीम को विस्तार दिया है।

साथ ही 16 राष्ट्रीय सचिवों की सूची में भी व्यापक क्षेत्रीय संतुलन दिखाई देता है। कविता पाटीदार, के. सुरेंद्रन, डॉ. भोला सिंह, डॉ. प्रदीप वर्मा, जगदीश ईश्वरभाई पटेल, आम आदमी पार्टी से भाजपा में आये डॉ. संदीप पाठक और फांगनॉन कोन्याक, संगीता यादव, अनिल एंटनी, डॉ. एम. वेंकटेशन, मनोज तिग्गा, सिद्धार्थ शंभू, डॉ. स्वदेश सिंह, मृगांका देब बर्मन, रोहन गुप्ता और जय प्रकाश को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इनमें दक्षिण, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत, हिंदी पट्टी और शहरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, सभी को जगह मिली है।

नई टीम के अन्य हिस्से भी राजनीतिक संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय कार्यालय प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय कार्यालय सचिव महेंद्र पांडे बनाए गए हैं। नॉर्थ-ईस्ट कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी डॉ. संबित पात्रा और संयुक्त कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी राजीव बब्बर को दी गई है। सभी सेल्स के समन्वय की कमान विष्णु दत्त शर्मा को मिली है, जबकि ऋतुराज सिन्हा और विष्णु वर्धन रेड्डी संयुक्त समन्वयक होंगे।

मोर्चों की कमान भी सामाजिक और चुनावी विस्तार को ध्यान में रखकर तय की गई है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. हेमंग जोशी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष अमरपाल मौर्य, किसान मोर्चा के अध्यक्ष बंसीलाल गुर्जर, एससी मोर्चा के अध्यक्ष शिवेश कुमार राम, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष डॉ. मन्नालाल रावत और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बसीत अली बनाए गए हैं। इससे भाजपा ने समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच संगठनात्मक पहुंच को मजबूत करने की कोशिश की है।

वित्तीय मोर्चे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राजस्थान के राजेश मंगल को संयुक्त कोषाध्यक्ष बनाया गया है। पीयूष गोयल के प्रशासनिक और आर्थिक अनुभव का लाभ संगठन के वित्तीय प्रबंधन को मिल सकता है। पीयूष गोयल पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। यहां सवाल यह है कि अब देखना यह होगा कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को महत्व देने वाली भाजपा क्या पीयूष गोयल से केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ने को कहती है या फिर वह दोनों पदों पर बने रहेंगे? कुल मिलाकर नितिन नबीन की टीम का संदेश साफ है कि भाजपा अब संगठन को केवल पदाधिकारियों की सूची के रूप में नहीं, बल्कि चुनावी मशीनरी के रूप में कसना चाहती है। राम माधव की रणनीतिक समझ, वसुंधरा राजे का जनाधार, स्मृति ईरानी की आक्रामक राजनीतिक शैली, सुनील बंसल का संगठनात्मक अनुभव, पीयूष गोयल की प्रशासनिक क्षमता और दक्षिण-पूर्वोत्तर से आए नेताओं का क्षेत्रीय अनुभव पार्टी के लिए अलग-अलग मोर्चों पर उपयोगी साबित हो सकता है।

लेकिन असली चुनौती भी यहीं से शुरू होती है। अलग-अलग क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं वाले नेताओं को एक सूत्र में बांधना, राज्यों में गुटबाजी को नियंत्रित करना, डिजिटल नैरेटिव को विपक्ष के हमलों के सामने प्रभावी बनाना, संगठन और सरकार के बीच तालमेल कायम रखना और आगामी चुनावों में इन नियुक्तियों के जरिये साधे गये सामाजिक समीकरणों को वास्तविक वोटों में बदलना आसान नहीं होगा। नितिन नबीन ने टीम चुन ली है; अब इस टीम को परिणाम देने वाली राजनीतिक ताकत में बदलना उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

मक्का समझौते से क्यों खुश हुए ट्रंप?

विकास मिश्रा

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प की खुशी ने सबको चौंका दिया है। पहले माना जा रहा था कि इस रक्षा समझौते के पीछे मध्य-पूर्व में अमेरिकी छत्रछाया को लेकर बढ़ता अविश्वास है। मगर अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इसमें भी अमेरिकी चालबाजी है? और हम यदि अपने नजरिये से देखें तो यह सोचना जरूरी है कि भारत के लिए इस रक्षा समझौते से क्या कुछ खास बदलेगा? क्या यह वाकई हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए? सबसे पहले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भाषा पर गौर करिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- तीनों देशों के महान नेतृत्व को बधाई। यह एक बड़ा, मजबूत और अहम कदम है- वाह! ट्रम्प की भाषा में कितनी खुशी झलक रही है ना! अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, तीनों ही अमेरिकी खेमे के देश रहे हैं। हां, तुर्की ने रूस से एस-400 रक्षा प्रणाली खरीदी तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाए और उसे एफ-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से बाहर कर दिया। मगर अब ट्रम्प संदेश दे रहे हैं कि तुर्की को यह विमान मिल सकता है। जाहिर सी बात है कि तीनों ने जो समझौता किया है, उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिकी सहमति का अंदेशा होता है। इसके साथ ही क्या आपने इस रक्षा समझौते के एक पेंच पर ध्यान दिया? पाकिस्तान और सऊदी अरब तो दोस्त रहे हैं लेकिन तुर्की के साथ सऊदी की नहीं बनती है। कई फोरम पर दोनों एक-दूसरे के खिलाफ रहे हैं। इतना ही नहीं एक तरफ सऊदी अरब चाहता है कि इस्लामी दुनिया के नेतृत्व का झंडा उसके पास रहे तो दूसरी तरफ यह चाहत तुर्की की भी रही है। एक घटना याद दिलाता हूं आपको। बात करीब छह साल पुरानी है। तुर्की की जनरल असेंबली में राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने आरोप लगाया कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को निशाना बना रहे हैं। उनका इशारा सऊदी अरब की ओर था। इसके बाद काउंसिल ऑफ सऊदी चेंबर्स के चेयरमैन अजलान अल अजलान ने आह्वान किया कि सऊदी के हर नागरिक को तुर्की का हर तरह से बहिष्कार करना चाहिए। करीब सात साल पहले पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने एक रक्षा समझौते की कोशिश की थी लेकिन उसे सऊदी अरब ने ही पलीता लगाया था। निश्चय ही एक-दूसरे की खिलाफत करने वाले प्रतिस्पर्धी देश सऊदी अरब और तुर्की साथ आ गए तो इसके पीछे वक्त की मजबूरी और अमेरिका का दबाव ही महत्वपूर्ण कारण है। तुर्की को एफ-35 लड़ाकू विमान की चाहत है और ट्रम्प को खुश करने के लिए अर्दोआन कुछ भी करने को तैयार हैं। जहां तक सऊदी अरब की बात है तो पाकिस्तान के साथ पहले भी उसका सैन्य समझौता रहा है। पाकिस्तान की कुछ सैन्य टुकड़ियां सऊदी अरब में हमेशा तैनात भी रही हैं लेकिन हाल ही में जब ईरान ने सऊदी अरब के भीतर कुछ ठिकानों पर हमला किया तो पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी काम नहीं आई। क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि उसने जरा सी भी हरकत की तो ईरान उसे नाकों चने चबवा देगा। यह कहा जा सकता है कि पहले सऊदी और पाकिस्तान में जो समझौता था, वो कामचलाऊ स्तर का था लेकिन मक्का समझौते में तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि तुर्की, पाकिस्तान या सऊदी अरब में से तीनों पर कोई हमला होता है तो यह तीनों पर हमला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में जंग में भागीदारी जरूरी मानी जाएगी। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब पाकिस्तान और भारत के बीच जंग छिड़ जाए! लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या भारत के खिलाफ जंग में सऊदी अरब शामिल होगा? मुझे लगता है कि सऊदी अरब के सामने यह स्थिति कभी नहीं आएगी क्योंकि भारत कभी किसी पर हमला करता ही नहीं है! ध्यान रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर हमला नहीं था बल्कि आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने की कार्रवाई थी। हकीकत यही है कि जब भी हमला किया है तो पाकिस्तान ने ही किया है। समझौते में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि हमला तीनों मिलकर करेंगे। और जहां तक सऊदी अरब के साथ भारत के संबंधों का सवाल है तो यह निरंतर मधुर होता गया है।

प्रशांत और चिराग के बीच पक रही सियासी खिचड़ी के निहितार्थ

कमलेश पांडे

बिहार में जन सुराज पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बीच जो राजनीतिक खिचड़ी पकने की चर्चा है, वह उत्तरप्रदेश की राजनीति से अभिप्रेरित है। चूंकि प्रशांत किशोर मशहूर चुनावी रणनीतिकार भी हैं और लगभग सभी प्रमुख पार्टियों के रणनीतिक घाटों की पानी का स्वाद चख चुके हैं, इसलिए उनसे जुड़ी इस आशय की चर्चा भी अनायास नहीं है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सामाजिक न्याय क्रांति और मंडल बनाम कमंडल की मतलबी राजनीति की कड़ी में जहां उत्तरप्रदेश में चार-चार बार दलित नेत्री सुश्री मायावती को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और उनकी बहुजन समाज पार्टी तीन बार गठबंधन के तहत और एक बार पूर्ण बहुमत से यूपी की सत्ता में आई। लेकिन बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, जदयू के हुक्मरान नीतीश कुमार ने लोजपा के राम विलास पासवान और उनके पुत्र चिराग पासवान को कभी पूर्ण रूप से उभरने ही नहीं दिया और गठबंधन में भी कमजोर बनाए रखा।

यही वजह है कि बिहार में नए जमाने की राजनीति के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के साथ गठबंधन की सम्भवनाओं को हवा दिलवाकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव के समक्ष एक तगड़ी चुनौती पेश करने की अपनी मंशा उजागर कर दी है। चिराग पासवान जिस तरह से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान करार देते हैं, इससे उनकी भी बेचैनी बढ़ेगी हो।

यह ठीक है कि जन सुराज पार्टी और लोजपा रामविलास के बीच किसी औपचारिक गठबंधन की सार्वजनिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगस्त 2026 की ताजा राजनीतिक हलचल को देखें तो दोनों के बीच संभावित सियासी तालमेल की चर्चा को महज अफवाह मानकर खारिज करना भी जल्दबाजी होगी। क्योंकि हाल की रिपोर्टों में दोनों के करीब आने और भाजपा-राजद से अलग एक संभावित धुरी की चर्चा सामने आई है। इससे एनडीए की राजनीति में चिराग पासवान का रुतबा बढ़ना भी स्वाभाविक है। फिर भी यदि चिराग पासवान को दलित मुख्यमंत्री बनाने के स्वप्न प्रशांत किशोर यदि दिखाते हैं, या

फिर उपमुख्यमंत्री पद का भी सियासी चारा डालते हैं तो मिशन 2029 के संसदीय चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए और महागठबंधन के हाथपांव फूलना स्वाभाविक है। आइए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मनोवांछित सियासी खिचड़ी में क्या-क्या पक रहा है? और इसके राजनीतिक स्वाद के मिजाज से इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं-

पहला, लोजपा युवराज चिराग पासवान के लिए यह एनडीए के भीतर दबाव की राजनीति हो सकती है, क्योंकि चिराग पासवान पहले भी सीट बंटवारे और एनडीए के भीतर अपनी राजनीतिक हैसियत को लेकर स्वतंत्र रुख दिखाते रहे हैं। 2025 में भी उनके प्रशांत किशोर से संभावित संपर्क की खबरें सामने आई थीं। इसलिए सियासत में हर खुली हुई सम्भवनाओं और उससे बनने बिगड़ने वाली हवा से इंकार नहीं किया जा सकता है।

दूसरा, जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण सामाजिक-पॉलिटिकल पुल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जन सुराज अपने को भाजपा और आरजेडी—दोनों से अलग विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब बांकीपुर में किशोर की जीत ने उन्हें सिर्फ आंदोलनकारी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय चुनावी ताकत के रूप में भी स्थापित किया है।

तीसरा, सबसे दिलचस्प संभावना है—माइनस भाजपा, माइनस आरजेडी राजनीति। यानी कि ताजा राजनीतिक चर्चाओं में इसी तरह के पुनर्संयोजन की संभावना उठ रही है। इसका अर्थ होगा कि चिराग पासवान अपना दलित/पासवान प्रभाव और जन सुराज पार्टी अपना युवा, गैर-पारंपरिक तथा शहरी-मध्यवर्गीय आधार जोड़ने की कोशिश करे। दोनों ने यदि रणनीतिक रूप से सवर्णों को तरजीह दी तो भाजपा/कांग्रेस के लिए यह किसी झटके की तरह होगा।

लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों की राजनीतिक जरूरतें अलग अलग हैं। चाहे चिराग पासवान हों या प्रशांत किशोर, दोनों अपना स्वतंत्र राजनीतिक स्पेस बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही खुद को तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जहां चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए अपना बारगेनिंग पॉवर बढ़ाना चाहते हैं, वहीं प्रशांत किशोर भाजपा और आरजेडी दोनों से दूरी दिखाना चाहते हैं। इस बात में कोई दो राय नही कि उत्तरप्रदेश के जाटवों के वोट बैंक के तरह ही बिहार में भी पासवान वोट का मजबूत आधार है, जबकि प्रशांत किशोर युवा, शिक्षित और बदलाव चाहने वाले मतदाताओं पर जोर देते हैं। वह संगठन और चुनावी नेटवर्क के कार्यसाधक हैं। उनमें नया राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने और अभियान चलाने की अद्भुत क्षमता है। लिहाजा यहीं से असली सवाल पैदा होता है—क्या चिराग एनडीए के भीतर रहकर जन सुराज से तालमेल करेंगे, या भविष्य में कोई व्यापक वैकल्पिक मोर्चा बनेगा?

अलबत्ता, इन चर्चाओं में एक और बड़ा संकेत निहित है। वह यह कि प्रशांत किशोर अब केवल विधानसभा की राजनीति तक सीमित नहीं दिख रहे, बल्कि जन सुराज की नजर विधान परिषद के चुनावी क्षेत्रों पर भी बताई जा रही है। यानी संगठन को लगातार चुनावी मशीनरी में बदलने की कोशिश हो रही है।

दूसरी ओर चिराग पासवान ने भी हाल के दिनों में ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन पर सरकार/एनडीए के भीतर असहजता पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, उन्होंने गत दिनों बिहार की शराबबंदी नीति की प्रभावशीलता पर खुलकर सवाल उठाया। यानी दोनों के बीच संभावित तालमेल का आधार केवल जातीय गणित नहीं, बल्कि एंटी-एस्टैब्लिशमेंट और नया विकल्प का राजनीतिक नैरेटिव भी बन सकता है।

मगर सबसे बड़ी अड़चन भी यही है। खासकर प्रशांत किशोर की राजनीति का मूल दावा ही है कि वे पारंपरिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से अलग व्यवस्था खड़ी करेंगे। 2025 में उन्होंने चिराग के साथ गठबंधन की संभावना को सार्वजनिक रूप से नकारते हुए कहा था कि उनका गठबंधन जनता के साथ है। इसलिए यदि आज दोनों के बीच नजदीकी बढ़ती है, तो इसे सीधा चुनावी गठबंधन मानने के बजाय रणनीतिक संवाद समझना ज्यादा उचित होगा।

शुभेंदु सरकार के 100 दिन: क्या बदला, क्या मिला?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

सत्ता परिवर्तन के बाद सबसे बड़ा सवाल- क्या बदला? पश्चिम बंगाल में 2026 का सत्ता परिवर्तन सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं है। लंबे तृणमूल शासन के बाद भाजपा की सरकार और शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना राज्य की राजनीति में बुनियादी बदलाव है। 9 मई को शपथ लेने वाली सरकार के सामने सबसे पहली चुनौती थी कि चुनावी नारों और वादों को प्रशासनिक फैसलों में बदला जाए। पहले 100 दिनों में सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसकी प्राथमिकताएं पिछली सरकार से अलग हैं। आयुष्मान भारत को लागू करना, महिला-केंद्रित अन्नपूर्णा योजना, उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों की तैयारी और केंद्र के साथ बेहतर तालमेल इसी बदलाव का हिस्सा हैं।

सरकार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में आयुष्मान भारत को पश्चिम बंगाल में लागू करना है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य के करोड़ों लोगों को देशभर में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र से करीब 3,000 करोड़ रुपये की मंजूरी और शुरुआती 500 करोड़ रुपये जारी होने की बात भी सामने आई है। राजनीतिक दृष्टि से इसका महत्व और अधिक है। ममता बनर्जी सरकार की स्वास्थ्यसाथी योजना के समानांतर अब आयुष्मान भारत राज्य की नई स्वास्थ्य नीति का चेहरा बन रहा है। लेकिन सरकार की वास्तविक परीक्षा तब होगी, जब गरीब मरीज बिना कागजी जटिलताओं के अस्पताल में इसका लाभ उठा पाएंगे।

अन्नपूर्णा योजना शुभेंदु सरकार की दूसरी बड़ी राजनीतिक और सामाजिक पहल है। रिपोर्टों के अनुसार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3,000 रुपये मासिक सहायता देने का प्रावधान है और बड़ी संख्या में लाभार्थियों को भुगतान शुरू किया गया है। हालांकि बड़ी संख्या में आवेदनों की जांच और कुछ आवेदन खारिज किए जाने से पात्रता तथा सत्यापन की चुनौती भी सामने आई है। यहां राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बंगाल की चुनावी राजनीति में महिला मतदाता निर्णायक रहे हैं। इसलिए

अन्नपूर्णा योजना सिर्फ कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भाजपा के नए सामाजिक आधार को मजबूत करने का प्रयास भी है। आने वाले वर्षों में यह देखना होगा कि योजना आर्थिक रूप से कितनी टिकाऊ रहती है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा वादा रोजगार और औद्योगिक पुनरुद्धार का था। नई सरकार निवेश-अनुकूल माहौल बनाने के लिए औद्योगिक और भूमि नीति में बदलाव की तैयारी कर रही है। टाटा समूह के साथ करीब 28,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश पर बातचीत को सरकार अपने उद्योग एजेंडे की बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रही है।

लेकिन यहां सरकार को सावधानी से चलना होगा। निवेश की घोषणा और वास्तविक निवेश में अंतर होता है। जमीन पर कारखाना, उत्पादन और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार शुरू होने तक किसी भी निवेश प्रस्ताव को उपलब्धि मानना जल्दबाजी होगी। बंगाल की अर्थव्यवस्था के लिए अगले दो-तीन साल इस सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होंगे।

भाजपा लंबे समय से बंगाल में राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और प्रशासन के राजनीतिकरण का मुद्दा उठाती रही है। इसलिए सत्ता में आने के बाद शुभेंदु सरकार के लिए कानून-व्यवस्था केवल सामान्य प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक विश्वसनीयता का प्रश्न है। हाल के दिनों में पुलिस हिरासत में मौत के मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई और मुख्यमंत्री का पीड़ित परिवार से मिलना यह संकेत देता है कि सरकार जवाबदेही दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक टकराव और हिंसा की घटनाएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। इसलिए 100 दिनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि बंगाल की राजनीतिक हिंसा का दौर समाप्त हो गया है। सरकार को निष्पक्ष पुलिसिंग और कानून का समान अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

शुभेंदु सरकार ने प्रशासनिक बदलाव के साथ प्रतीकों की राजनीति में भी परिवर्तन किया है। 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने का फैसला इसी राजनीतिक-सांस्कृतिक बदलाव का उदाहरण है। यह ममता बनर्जी सरकार के खेला होबे दिवस से अलग राजनीतिक संदेश देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस जैसे बंगाल के राष्ट्रवादी प्रतीकों को लेकर सरकार की सक्रियता भी भाजपा के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वह बंगाली अस्मिता को राष्ट्रवादी राजनीति के साथ जोड़ना चाहती है। खुदीराम बोस की जन्मभूमि के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये की योजना इसका एक उदाहरण है।

सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया और युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में अवसर पैदा करना अभी लंबी चुनौती है। उद्योगों के लिए जमीन, निवेशकों का भरोसा, बिजली-पानी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना भी समय मांगता है।

दूसरी चुनौती वित्तीय स्थिति है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अगले एक-दो वर्षों में राज्य वित्तीय रूप से मजबूत होगा और सरकार कारोबारी माहौल सुधारने की दिशा में काम कर रही है। लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के बीच वित्तीय संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। शुभेंदु अधिकारी की सरकार को अब दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना है। एक तरफ उसे अपने समर्थकों की अपेक्षाएं पूरी करनी हैं और दूसरी तरफ उन मतदाताओं को भरोसा दिलाना है जिन्होंने बदलाव के लिए भाजपा को वोट दिया लेकिन अब सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक आधार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सरकार की हर प्रशासनिक चूक राजनीतिक मुद्दा बनेगी और हर उपलब्धि को विपक्ष चुनौती देगा। यही कारण है कि शुभेंदु सरकार के लिए पहले 100 दिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर हैं, लेकिन निर्णायक नहीं।

भारत में पाकिस्तानियों को मिल गई नागरिकता?

डॉ. रमेश ठाकुर

किसी पाकिस्तानी को आज के दौर में हिंदुस्तान में बसाना, उन्हें पनाह देना या फिर नागरिकता देनी वाली बात, शायद ही किसी के गले उतरे? बसाना तो दूर, ऐसा सोचना मात्र भी, सूरज का पूरब की जगह पश्चिम से निकलने जैसा माना जाएगा। पर, यह कोरी कल्पना पिछले दिनों हकीकत में तब्दील हुई। भारत में 56 साल पहले आए पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई है। वह भी एकाध लोगों को नहीं, बल्कि हजारों को। सरकार ने पिछले महीने बकायदा एक रंगारंग कार्यक्रम कर, ढोल-नगाड़े बजाकर विस्थापित पाकिस्तानियों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे। ताज्जुब यह भी है कि ऐसा चमत्कार हुकूमत ने ऐसे माहौल में किया, जब समूचे भारत में विभिन्न देशों के घुसपैठियों को निकालकर उन्हें खदेड़ने का अभियान केंद्रीय व राज्य स्तरों पर छिड़ा हो। इस अभियान की बानगी हमने हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। जब दो बॉर्डर राज्य, असम और पश्चिम बंगाल, का चुनाव इसी मसले के इर्दगिर्द घूमा। घुसपैठियों के अलावा भारत में कुछ वर्षों से एनआरसी और सीएए का भी शोर है। बावजूद इसके सरकार ने पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का बड़ा जाखिम उठाया। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? हालांकि, इस फैसले के सियासी मायने बहुतेरे हैं, जिसकी तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई भी देगी। सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांसुरी निमार्ण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों से नागरिकता मांगते आए हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1959 से 1971 के बीच पाकिस्तान से पीड़ित होकर कुछेक परिवार भारत आए थे। शुरूआत में यह परिवार कई राज्यों में भटकते रहे, कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बाद में यही जिला मुफीद लगा। पीलीभीत के अलावा कुछ नागरिकता रामपुर और बिजनौर में बसे विस्थापितों को भी दी गई है।

पीलीभीत के जिस क्षेत्र में यह परिवार रहते आए हैं वह जगह कभी विरान होती थी। इन लोगों ने इसे रहने लायक बनाया और उबड़खाबड़ जगहों पर मेहनत करके उसे खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया। आज इस क्षेत्र में अच्छी फसलें उगती हैं। सभी के पास कागजी दस्तावेजों के रूप में भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पहले से मौजूद हैं। साथ ही लंबे वक्त से मतदान भी करते आए हैं। लेकिन नागरिकता और मालिकाना हक से वंचित थे, जिसे मौजूदा योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये परिवार पीलीभीत जिले के अमरिया, न्यूरिया, शारदा डैम की तलहटी सहित आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। सरकार ने उन्हें खेती और आवास के लिए जमीन तो पहले से दी हुई हैं। लेकिन मालिकाना हैसियत नहीं दी, जिसके लिए यह लोग दशकों जद्दोजहद कर रहे थे। प्रत्येक चुनावों में इनसे के झूठा आश्वासन हुआ। पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने भी इनको नागरिकता दिलवाने का दिलासा दिया। पर, कुछ राजनैतिक अड़चनों के चलते वादा पूरा नही कर पाए। पिछले महीने 29 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में दौरा हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने इनको ना सिर्फ नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे, बल्कि मालिकाना हक के सरकारी कागज भी दिए। यह फैसला चुनाव के ऐन वक्त लिया गया। प्रदेश में मात्र 6-7 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश की राजनीति जमकर गर्माई हुई है। विपक्षी पार्टियों ने सीधे-सीधे एक बड़े वोटबैंक को साधने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाया है। पाकिस्तानी विस्थापियों को बसाने का यह पहला चरण है, अभी दूसरा चरण शेष है। 35 हजार लोग और हैं जो बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर, बिजनौर जैसे जिलों में बसे हैं। सभी को चिंहित किया जा चुका है, अगले कुछ महीनों बाद इन्हें भी मुकम्मल नागरिकता देने का फैसला हो चुका है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश के करीब सात-आठ जिलों में कुल 55 हजार विस्थापित पाकिस्तानियों की आबादी है, इनमें प्रत्येक वर्ष तेजी से इजाफा भी हो रहा है। 56 वर्ष पहले धार्मिक प्रताड़ना के रूप में मात्र 12 हजार 380 लोग आए थे।

देवों के पितामह ब्रह्मदेव

पुराणों में ब्रह्मा का स्वरूप विष्णु के सदृश ही निरूपित किया गया है। वह ज्ञान-स्वरूप, परमेश्वर, अज, महान, तथा सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और अंतर्रात्मा बतााए गए हैं...

त्रिदेवों में ब्रह्मा प्रमुख देवता हैं। इन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। इस कारण ब्रह्मा जी चतुर्मुख नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका निवास स्थान ब्रह्मालोक है। ब्रह्मा जी वैदिक प्रजापति के रूप का विकास हैं। प्रजापति की समस्त वैदिक गाथाएं ब्रह्मा जी पर आरोपित कर ली गई हैं। प्रजापति और उनकी दोहिता की कथा पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में वर्णित हुई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार क्षीरसागर में शेषशायी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इसलिए वह स्वयंभू कहलाते हैं। प्रकट होने के पश्चात ब्रह्मा ने घोर तपस्या करके ब्रह्माण्ड की सृष्टि की। वास्तव में सृष्टि ही ब्रह्मा का प्रमुख कार्य है। सावित्री इनकी पत्नी और सरस्वती पुत्री हैं। इनका वाहन हंस है। ब्रह्मा पुराणों में ब्रह्मा का स्वरूप विष्णु के सदृश ही निरूपित किया गया है। वह ज्ञान-स्वरूप, परमेश्वर, अज, महान, तथा सम्पूर्ण प्राणियों के जन्मदाता और अर्न्तरात्मा बतााए गए हैं। कार्य, कारण और चल-अचल सभी इनके अन्तर्गत हैं। समस्त कला और विद्या इन्होंने ही प्रकट कीं। ये त्रिगुणात्मक माया से अतीत ब्रह्मा हैं। यह हिरण्यगर्भ हैं और सारा ब्रह्माण्ड इन्हीं से निकला है। यद्यपि ब्राह्म पुराणों में त्रिदेवों के अन्तर्गत ये अग्रगण्य और प्रथम बने रहे, किन्तु धार्मिक संप्रदायों की दृष्टि से इनका कोई अलग संप्रदाय नहीं बन पाया। वृद्ध पिता की भांति इनका देव परिवार में स्थान उपेक्षित होता गया। जबकि ब्रह्मा सपूर्ण चराचर जगत के प्रकटकर्ता हैं।

ब्रह्मा की उत्पत्ति : महाप्रलय के बाद भगवान नारायण दीर्घ काल तक योगनिद्रा में मग्न रहे। योगनिद्रा से जगने के पश्चात उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ, जिसकी कार्णिकाओं पर स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने अपने नेत्रों को चारों और घुमाकर शून्य में देखा। इस चेष्टा से चारों दिशाओं में इनके चार मुख प्रकट हुए। जब चारों और देखने पर भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो उन्होंने विचार किया, इस कमल पुष्प पर बैठा हुआ मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं तथा यह कमल कहां से निकला है। तब ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की। उन्हें शेषशैय्या पर बैठे विष्णु भगवान के दर्शन हुए। अपने एवं विश्व के कारण परम पुरूष का दर्शन करके उन्हें प्रसन्नता हुई और उन्होंने विष्णु भगवान की स्तुति अनेक प्रकार से की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा कि अब आप तप शक्ति से सपन्न हो गए हैं और आपको मेरा अनुग्रह भी प्राप्त हो गया है। अत: आप सृष्टि को उत्पन्न करने का कार्य आरभ करें।

तब भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने अपने कमडंल से जल लेकर अभिमंत्रित करके उसे सभी दिशाओं में छिड़क दिया तथा सृष्टि की उत्पत्ति करने लगे। विष्णु भगवान की प्ररेणा से सरस्वती देवी ने ब्रह्म जी को सपूर्ण वेदों का ज्ञान कराया। ब्रह्मा जी मानसिक संकल्प से प्रजापतियों को उत्पन्न कर उनके द्वारा सपूर्ण प्रजा की सृष्टि करते हैं। इसलिए वह प्रजापतियों के भी पिता कहे गए हैं। समस्त प्रजापतियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है। दस मुख्य प्रजापति : मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मृगु, वशिष्ठ, दक्ष और कर्दम ये दस मुख्य प्रजापति हैं। सभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इन्हें उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। भगवत पुराणों के अनुसार भगवान रूद्र भी ब्रह्माजी के ललाट से उत्पन्न हुए। मानव सृष्टि के मूल महाराज मनु ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से उत्पन्न हुए और वाम भाग से मनु की पत्नी की उत्पत्ति हुई। स्वायंभु मनु और उनकी पत्नी से ही मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ हुई। सभी देवता ब्रह्मा जी के पौत्र माने गए हैं। अत: वह पितामह के रूप में जाने जाते हैं। वैसे ब्रह्मा देवता, दानव, तथा सभी जीवों के पितामह हैं। फिर भी वह विशेष रूप से धर्म के पक्षपाती हैं। जब देवासुर संग्रामों में पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं, वह धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। अत: भगवान विष्णु के 24 अवतारों में यह ही निमित्त बनते हैं। शैव तथा शाक्त आगमों की भांति ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक वशिष्ट सप्रदाय है, जो वैखानस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। परन्तु ये संप्रदाय अन्य संप्रदायों की अपेक्षा सीमित ही रहा। जबकि वैखानस संप्रदाय की सभी संप्रदायों में मान्यता आवश्य है। पुरूणादि सभी शास्त्रों के यह ही आदि वक्ता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी की प्राय अर्मूत उपासना ही होती है। सर्वतोमद, लिंगतोभद्र आदि चक्रों में उनकी पूजा अमूर्त रूप से होती है। मूर्तरूप में इनकी पूजा केवल पुष्कर तथा ब्रह्मावर्त क्षेत्र (बिठुर) में ही होती है, जहां सत्युग के समय का पीपल आज भी हरा भरा है। शास्त्रों में वर्णित है कि यहां ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी।

दानवों के उपास्य : माध्य सप्रदाय के आदि आचार्य भगवान ब्रह्मा जी माने जाते हैं। इसलिए आदि मुय मध्यपीठों में इनकी पूजा-आराधना की विशेष परंपरा है। देवताओं तथा असुरों की तपस्या में प्राय: सबसे अधिक वरदान आदि काल में ब्रह्मा ने ही दिए हैं।

'ॐ नम: शिवाय' से मिलती है ऊर्जा

ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारूकमेव बंधनात मृत्योमोक्षिमार्मतात...
नार्गद्रहराय, त्रलोचनाय, भस्मंगारागाय महेश्वराय...

इन स्त्रोतों से श्रावण माह गुंजायमान है। भगवान सदाशिव की कृपा का पात्र बनने के लिए बुजुर्गों के साथ-साथ युवा वर्ग भी इन दिनों शिव आराधना में लीन है। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही व्रत रखने का चलन भी युवाओं में काफी जोरों पर हैं। कई युवा तो ऐसे भी हैं जो पूरे महीने भर के श्रावण का व्रत करने को लेकर काफी उत्सुक है और वे इस धर्म का पालन भी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं।

शिव मंदिरों में भगवान को जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालु महिला, पुरुष व युवाओं और बच्चों की लंबी कतारें लगी रहती है। भूतभावन भोले के अभिषेक में खास तौर पर श्रद्धालु पंचगव्य, धतूरा, कनेर, बिल्वपत्र, शमीपत्र, आक के फूलों को अर्पित कर शिव आराधना में लीन है।

जीवन को सद्गति देते हैं शिव

-विनोद केशरवानी कहते हैं कि वेदों में उल्लेख किया गया है कि इस सृष्टि में शिव के समान दूसरा कोई दाता नहीं है। मैं हर बार श्रावण में भगवान के दर्शन करने जाता हूं। मुझे लगता है यही एक रास्ता है अपने जीवन को सद्गति देने का।

मन को मिलती है शांति

-बलराम यादव कहते हैं मेरा खुद का व्यवसाय है। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब भोलेनाथ ही कृपा है। इसीलिए में व्रत रखता हूं और श्रावण में दर्शन जरूर आता हूं। शिव मंदिर में आकर मन को शांति मिलती है।

ॐ नम: शिवाय कहने से ऊर्जा का संचार

-वीरेन्द्र चौधरी के अनुसार मैं प्राइवेट जॉब करता हूं और मुझे लगता है कि

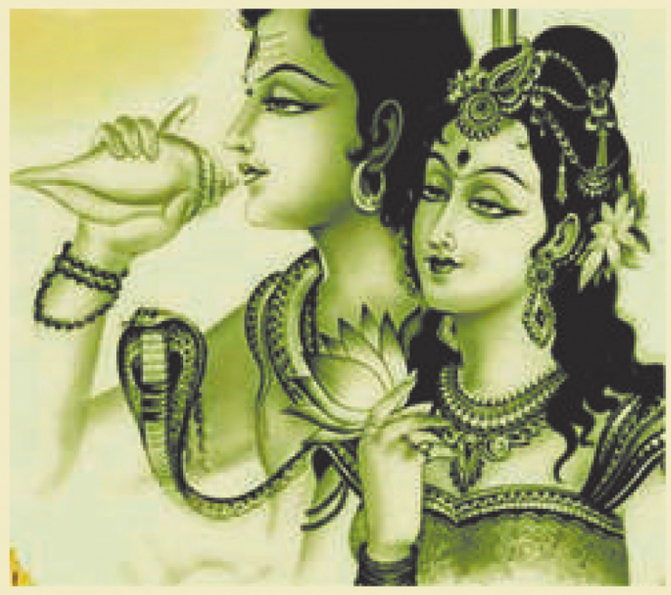

शिव आराधना से बढ़कर कोई और रास्ता नहीं शांति पाने का। सिर्फ ॐ नम: शिवाय कहने भर से ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसीलिए मैं पूरे श्रावण के महीने में शिव के दर्शन करने मंदिर जरूर जाता हूं।

मैं श्रावण सोमवार का व्रत सालों से करता आ रहा हूं, शिवशंकर ने मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं।

युवाओं ने भी उत्साह के साथ महादेव की आराधना की और इस बात को सिद्ध कर दिया कि युवा मनों में भी आस्था की लौ जगमगा रही है।

शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय

भविष्यपुराण में ऐसा उल्लेख है कि शनि अमावस्या के दिन शनि का पूजन विशेष फलदायी होता है। जिन जातक की कुंडली या राशियों पर साढ़ेसाती व ढैया का प्रभाव है वे अच्छे फल प्राप्त करने के लिए 24 दिसंबर को पड़ने वाली शनिश्चरी अमावस्या पर शनिदेव का विधिवत पूजन कर पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। बताए गए उपाय सभी जातकों को सफलता दिलाएंगे।

ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री के अनुसार 24 दिसंबर को शनिश्चरी अमावस्या का मुहूर्त प्रात: 6.30 से प्रारंभ होकर रात्रि 3.40 तक रहेगा।

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए ये करें उपाय

- शनि अमावस्या के दिन या रात्रि में शनि चालीसा का पाठ, शनि मंत्रों का जाप एवं हनुमान चालीसा का पाठ करें।
- इस दिन पीपल के पेड़ पर सात प्रकार का अनाज चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
- तिल से बने पकवान, उड़द से बने पकवान गरीबों को दान करें।
- उड़द दाल की खिचड़ी दरिद्रनारायण को दान करें।
- अमावस्या की रात्रि में 8 बादाम और 8 काजल की डिब्बी काले वस्त्र में बांधकर संदूक में रखें।
- शनि यंत्र, शनि लॉकेट, काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें।
- इस दिन नीलम या कटैला रत्न धारण करें। जो फल प्रदान करता है।
- काले रंग का श्वान इस दिन से पालें और उसकी सेवा करें।

सर्वधर्म समभाव का प्रतीक स्वस्तिक

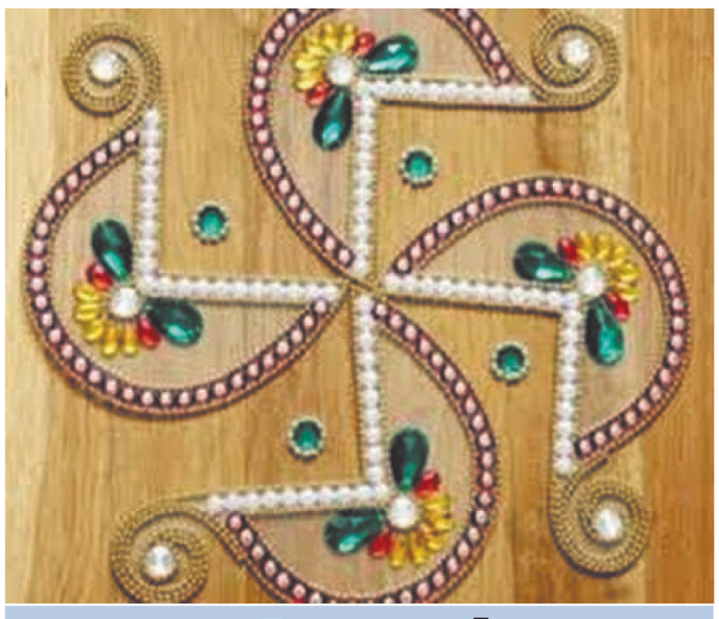

मांगलिक प्रतीक सकारात्मक उर्जा की खान होते हैं, जो हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ने की ताकत तो देते ही हैं, हमारी प्रगति की राहें भी सहज करते हैं। तभी लोग प्रतीकों को धारण करते हैं। इन्ही प्रतीकों में अहम है स्वस्तिक, जिसे दुनियाभर के तमाम धर्म, वर्ग और समाज में मांगलिक माना जाता है। अपने घर में, घर के मुख्य द्वार और वस्तुओं पर इस प्रतीकको अंकित करते हैं। इसके प्रयोग का उद्देश्य यही रहता है कि हमारे आसपास सकारात्मक उर्जा का संचार होता रहे और हमारा घर-परिवार खुशहाल, शांतिपूर्ण, प्रगतिशील रहे। जानिए, यह मांगलिक प्रतीक हमें क्या-क्या लाभ देता है -

स्वस्तिक मंत्र

किसी भी मंगल कार्य की शुरुआत स्वस्ति मंत्र उच्चारण के साथ की जाती है। यह मंत्र है-

ऊं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध-श्रवा-हा स्वस्ति न-ह पूषा विश्ववेदा- हा।
स्वस्ति न-ह ताक्षर्यो अरिष्टि-नेमि-हि स्वस्ति नो बृहस्पति-हि-दधातु ॥

महान कीर्ति वाले इंद्र हमारा कल्याण करो, विश्व के ज्ञानस्वरूप पूषादेव हमारा कल्याण करो। जिसका हथियार अटूट है ऐसे गरुड़ देव हमारा मंगल करो। बृहस्पति देव हमारा मंगल करो। यानी जहां शुभ, मंगल और कल्याण का भाव होता है, वहीं स्वस्तिक का वास होता है। इसे सरल रूप में देखें, तो जहां परिवार, समाज या रिश्तों में प्यार, सुख, श्री, उमंग, उल्लास, सद्भाव, सुंदरता और विश्वास का भाव हो।

स्वस्तिक शब्द सु एवं अस्ति का योग है। सु का अर्थ है... शुभ और अस्ति का अर्थ है होना। इस तरह स्वस्तिक अर्थात शुभ हो, कल्याण हो। स्वस्तिक किसी व्यक्ति, जाति या वर्ग का प्रतीक नहीं, यह समग्र विश्व का कल्याणकारक है और इसमें 'वसुधैवकुटुंबकम', यानी विश्व बंधुत्व की भावना निहित है। भारतीय संस्कृति में प्राचीनकाल से ही इसे विशेष महत्व दिया जाता है, मंगल का प्रतीक माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक चिह्न निर्मित कर उसका पूजन किया जाता है। अमरकोश में भी स्वस्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल या पुण्यकार्य करना बताया गया है। अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो।

आकृति का अर्थ

स्वस्तिक का रूपांकन छह रेखाओं के प्रयोग से होता है। स्वस्तिक में एक-दूसरे को काटती हुई दो सीधी रेखाएं होती हैं या स्वस्तिक बनाने के लिए धन चिह्न बनाकर उसकी चारों भुजाओं के कोने से समकोण बनाने वाली एक रेखा दाहिनी ओर खींचने से स्वस्तिक बन जाता है। यह रेखा खींचना लंबवत भुजा से प्रारम्भ करना चाहिए और इसमें दक्षिणवर्ती गति होती है। दिशाएं मुख्यत: चार हैं, खड़ी तथा सीधी रेखा खींचकर जो धन चिह्न जैसा आकार बनता है, यह चार दिशाओं का द्योतक सर्वत्र और सदैव यही माना गया है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी चार भुजाओं को चार दिशाओं की उपमा दी गई है। सिद्धांत सार ग्रंथ में उसे विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक चिह्न माना गया है। उसके मध्य भाग को विष्णु की कमल-नाभि और रेखाओं को ब्रह्माजी के चार मुख, चार हाथ और चार वेदों के रूप में निरूपित किया गया है। अन्य ग्रंथों में चार युग, चार वर्ण, चार आश्रम एवं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चार प्रतिफल प्राप्त करने वाली समाज व्यवस्था एवं वैयक्तिक आस्था को जीवंत रखने वाले संकेतों को स्वस्तिक में ओत-प्रोत बताया गया है। प्राचीन काल में राजा-महाराज द्वारा किलों का निर्माण स्वस्तिक के आकार में किया जाता रहा है, ताकि किले की सुरक्षा अभेद्य बनी रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्वस्तिकनुमा दुर्ग का निर्माण पूर्णत: वास्तु-सम्मत होता था।

पौराणिक महत्व

पुराणों के अनुसार स्वस्तिक में शक्ति, प्रगति, प्रेरणा और शोभा का समन्वय माना जाता है। इन्ही के समन्वय से यह जीवन और संसार समृद्ध बनता है। स्वस्तिक की चार भुजाओं को विष्णु की चार भुजाओं के रूप में माना गया है, जो विकास और विनाश के बीच संतुलन बनाकर सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान विष्णु अपने चारों हाथों से दिशाओं का पालन करते हैं। स्वस्तिक का केन्द्र-बिंदु है नारायण का नाभि-कमल, यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का उत्पत्ति-स्थल। इससे सिद्ध होता है कि स्वस्तिक सृजनात्मक है। स्वस्तिक की चारों भुजाओं को चारों दिशाओं के कल्याण की कामना के प्रतीक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, जिन्हें बाद में इसी भावना के साथ रेडक्रॉस सोसायटी ने भी अपनाया।

स्वस्तिक का लाल रंग

भारतीय संस्कृति में लाल रंग को बहुत शुभ माना जाता है और मांगलिक कार्यों में उसका प्रयोग सिंदूर, रोली या कुमकुम के रूप में किया जाता है। लाल रंग सजीवता का प्रतीक है और हमारे शरीर में व्याप्त होकर प्राण शक्ति का पोषक है। मूलत: यह रंग ऊर्जा, शक्ति, स्फूर्ति और महत्वाकांक्षा का संकेतक है। नारी के जीवन में इसका विशेष स्थान है और उसके सुहाग चिह्न व शृंगार में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है।

स्त्री की मांग का सिंदूर, माथे की बिंदी, हाथों की चूड़ियां, पांव का आलता-महावर, करवाचौथ की साड़ी, शादी का जोड़ा आदि के रूप में लाल रंग की महत्ता मौजूद है। नाभि स्थित मणिपुर चक्र का पर्याय भी लाल रंग है। शरीर में लाल रंग की कमी से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लाल रंग से ही केसरिया, गुलाबी, मेहरून और अन्य रंग बनाए जाते हैं। इन सब तथ्यों से प्रमाणित होता है कि स्वस्तिक लाल रंग से ही अंकित किया जाना चाहिए या बनाना चाहिए।

विश्वभर में मान्यता

स्वस्तिक को भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में विभिन्न स्वरूपों में मान्यता प्राप्त है। जर्मनी, यूनान, फ्रांस, रोम, मिस्र, ब्रिटेन, अमरीका, स्कैंडिनेविया, स्पेन, सीरिया, तिब्बत, चीन, साइप्रस और जापान आदि देशों में भी स्वस्तिक का प्रचलन है।

अधिकांश लोगों की मान्यता है कि स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक है। जैन धर्मावलंबी अक्षत पूजा के समय स्वस्तिक चिह्न बनाकर तीन बिंदु बनाते हैं। पारसी उसे चतुर्दिक दिशाओं एवं चारों समय की प्रार्थना का प्रतीक मानते हैं। व्यापारी वर्ग इसे शुभ-लाभ का प्रतीक मानते हैं।

बहीखातों में ऊपर की ओर श्री लिखा जाता है और उसके नीचे स्वस्तिक बनाया जाता है। भले ही विभिन्न देशों के रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा-पद्धतियों में भी जबतब परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह सच है कि सुख-समृद्धि एवं रक्षित जीवन के लिए दुनियाभर में कई जगह स्वस्तिक का इस्तेमाल किया जाता है।

समृद्धि लाती है लकी कैट

हर सभ्यता में पशु-पक्षियों के साथ अलग-अलग धारणाएं जुड़ी होती हैं। यह भी हो सकता है कि एक ही जानवर के बारे में अलग-अलग सभ्यताओं में परस्पर विपरीत धारणाएं देखने सुनने को मिलें। ऐसा ही बिल्ली के साथ है। फेंगशुई में बिल्ली को प्राचीन समय से ही शुभ माना जाता है। बिल्ली को धन-संपत्ति और लक्ष्मी जी के साथ भी जोड़ा जाता है। भारत में एक मान्यता यह भी है कि दीवाली की रात लक्ष्मीपूजन के समय बिल्ली का घर में आना या दिखाई देना समृद्धि सूचक होता है। भारत में ही नहीं, जापान, हांगकांग व सिंगापुर में भी बिल्ली को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। वहां बिल्ली के स्टेचू (टॉय, जिसमें बिल्ली का अगला एक पांव उठा हुआ प्रतीत होता है) अक्सर देखने को मिल जाती है। बिल्ली के इस स्टेचू को लकी कैट कहा जाता है, जिसे ऑफिस, घर व दुकान में रखना शुभ समझा जाता है। सौभाग्य व समृद्धि के लिए इसे घर और ऑफिस में रखा जाता है। सफेद और पीले रंग की बिल्ली को पश्चिम दिशा में रखने से समृद्धि आती है। परपल रंग की बिल्ली को मध्य भाग में रखने से पारिवारिक जीवन में मधुरता आती है। हरे रंग की बिल्ली उत्तर-पूर्व में रखने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, वहीं उत्तर दिशा में नीले रंग की बिल्ली दुर्भाग्य दूर करती है।

लकी कैट का इस्तेमाल कई अलग-अलग प्रयोजनों के लिए किया जाता है। दुर्भाग्य भगाने के लिए व सुख-संपन्नता पाने के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है। भारत में आमतौर पर लकी कैट गोल्डन कलर की मिलती है। इसे जमीन से 4-5 फुट ऊपर लगाना चाहिए। इसकी कीमत 300 रुपए से 1500 रुपए तक होती है। माना जाता है कि गोल्डन लकी कैट गोल्ड यानी सोने की तरह घर व कार्य- स्थल में संपन्नता की बरसात करती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

गुजरात केंद्रित मॉडल पर अन्नामलाई का हमला

चेन्नई। इंडिया टुडे तमिलनाडु राउंड टेबल में

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वी द लीडर्स के संस्थापक के. अन्नामलाई ने विकास के गुजरात-केंद्रित दृष्टिकोण की आलोचना की. उनका मानना है कि बड़ी कंपनियों के निवेश, नई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और बड़े राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय आयोजन सिर्फ एक ही राज्य में केंद्रित नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि इनका फायदा देश के अन्य राज्यों को भी मिलना चाहिए. अन्नामलाई ने यह भी कहा कि भाजपा की निर्णय प्रक्रिया तेजी से दिल्ली-केंद्रित होती जा रही है और उन्होंने राज्य स्तरीय नेताओं को अधिक अधिकार देने की बात करते हुए कहा- मुझे लगता है कि भाजपा के फैसले दिल्ली-केंद्रित होते जा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसे बदलना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य स्तर के नेताओं को निर्णय लेने और उन पर अमल करने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए. ईमानदारी से कहूं तो उन्हें कार्रवाई करने के लिए राज्य स्तरीय नेताओं को सशक्त बनाना ही होगा।

युवा शक्ति को बर्बाद कर रहा माफिया तंत्रः योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

माफिया तंत्र, नशे की लत और विपक्ष की राजनीति पर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने माफिया संस्कृति को युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया. सीएम योगी ने युवाओं को खेलों से जुड़ने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का भी संदेश दिया. सीएम योगी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचे थे. यहां उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों और विपक्ष पर निशाना साधा.मुख्यमंत्री ने कहा, उस समय की सरकारों के एजेंडे में खेल नहीं था, युवा नहीं था. आज जो लोग युवा-युवा करके चिल्ला रहे हैं, युवा इनके एजेंडे में कभी नहीं था, ये सिर्फ आपका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं. उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए आगे कहा, आपके हितों के लिए जब इनको मौका मिला था सत्ता में रहने का, तब इन्होंने आपके हितों के लिए कुछ नहीं किया।

अखिलेश ने बीजेपी सरकार की शिक्षा नीति पर उठाए सवाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ

में जयप्रकाश नारायण स्कूल के छात्र सड़कों पर उतर आए. स्कूल में टीचरों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इसे लेकर विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा. दुबग्गा क्षेत्र के बालागंज चौराहे पर बच्चों के सड़क पर उतरने से रोड पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया. जयप्रकाश नारायण स्कूल में पढ़ने वाले स्कूली बच्चों का आरोप है कि उनके स्कूल में लंबे समय से टीचरों की भारी कमी बनी हुई है. छात्रों का दावा है कि टीचरों के न होने से उनकी रोजाना की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो नाराज छात्र बालागंज चौराहे पर धरने पर बैठ गए. छात्रों के प्रदर्शन की वजह से चौराहे के चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और पूरे इलाके में ट्रैफिक थम गया।

काशी के अखाड़े में विदेशी पहलवान

काशी। नाग पंचमी पर सोमवार को देशभर

में कई अलग रंग दिखाई दिए. आस्था के इस पर्व का एक अनोखा रंग भगवान शिव की नगरी काशी में भी दिखाई दिया, जहां सात समंदर पार से विदेशी पहलवान अपनी शारीरिक क्षमताओं को परखने के लिए आए. आपको जानकर भले ही हैरानी होगी, लेकिन नागपंचमी पर काशी के अखाड़ों में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है. जहां सैकड़ों वर्षों से नाग पंचमी पर कुश्ती, जोड़ी, गदा और डंबल के जरिए पहलवान अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करते हैं. खास बात यह है कि अखाड़ों में विदेशी मेहमान भी आकर जोर-आजमाइश करते हैं. स्पेन के खेल मेसफ्लो के खिलाड़ी सेंटियागो जिन्हें सेंटी या शांति के नाम से भी जाना जाता है, यहां अपनी ताकत का नमूना पेश कर रहे हैं. वहीं, नीदरलैंड के हर्बर्ट ने जब अखाड़े में जोड़ी, गदा और डंबल फेरना शुरू किया तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.।

बिहार के मंदिर में भगदड़ 7 श्रद्धालुओं की मौत

पटना। बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध

अशोकधाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं पर बिजली का तार गिरने की अफवाह से अचानक भगदड़ मच गई. इस दर्दनाक हादसे में सात श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों को इलाके के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं, एक प्रत्यक्षदर्शी ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. घायलों को तुरंत लखीसराय सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस ने बताया हादसे में जान गंवाने वाले चार मृतकों की पहचान हो गई है. पुलिस के अनुसार, चार मृतक महिलाओं की पहचान 55 वर्षीय हेमलता, ललिता देवी, निवासी हलसी, 50 वर्षीय रिंकू देवी निवासी मुंगेर और 44 वर्षीय मनमाला देवी निवासी बड़हिया के रूप में हुई है. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के वक्त मंदिर परिसर में भारी भीड़ जमा थी. श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए कतार में लगे हुए थे।

नई टीम में चुनावी राज्यों पर भाजपा का बड़ा दांव

यूपी को सबसे अधिक तवज्जो, यहां ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय के बीच संतुलन साधा

नई दिल्ली/ लखनऊ/ चंडीगढ़। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम के गठन में चुनावी राज्यों पर बड़ा दांव खेला है। नवीन ने सबसे ज्यादा तवज्जो उत्तर प्रदेश को दी है, जहां से आठ नेताओं को अपनी टीम में शामिल किया है। लोकसभा चुनाव में झटके खा चुकी भाजपा ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े समुदाय पर सबसे ज्यादा दांव लगाया है।

नई टीम में तीन ओबीसी चेहरे हैं, जबकि दो मुस्लिम नेताओं को भी पद दिए गए हैं। पूर्वांचल से आने वाले ब्राह्मण चेहरे और बस्ती से दो बार के सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। यानी पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगह देने के साथ भाजपा ने अपने पारंपरिक सामाजिक आधार को भी साधने की कोशिश की है।

पार्टी पंजाब में सुखबीर बादल के रिश्तेदार मनप्रीत बादल के जरिये सिख समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश में है। उत्तराखंड में ब्राह्मण व ठाकुर समुदाय के बीच संतुलन साधकर पार्टी जीत का हैट्रिक लगाना चाहती है। नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश से दो महामंत्री, दो उपाध्यक्ष और दो मंत्री बनाए गए हैं।

दो नेताओं को ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नई टीम में जिन चेहरों को शामिल किया गया है, उसके जरिये यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से जहां जातिय समीकरण साधने की कोशिश की गई है वहीं, सपा के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की काट तैयार करने का भी प्रयास है।

पार्टी ने प्रो. तारिक मंसूर एवं कुंवर बासित अली को अहम जिम्मेदारी देकर अल्पसंख्यक कार्ड भी खेला है। बासित

अली संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े रहे और भाजपा के मुस्लिम संपर्क अभियान का चेहरा रहे। ओबीसी समाज की दो महिलाओं को भी राष्ट्रीय टीम में स्थान देकर आधी आबादी को भी साधने की कोशिश की गई है।

धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा को तीसरी बार संगठन में उपाध्यक्ष बनाया गया है। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने लंबे समय बाद संगठन में वापसी की है। बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को टीम में महामंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।

बुलंदशहर के सांसद और दलित चेहरे के तौर पर डॉ. भोला सिंह और ओबीसी चेहरा संगीता यादव को टीम में मंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्या को जहां ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है।

राज्यों और सामाजिक समीकरणों का ध्यान साफ दिखता है। राजस्थान से सतीश पूनिया, मध्यप्रदेश से गजेंद्र पटेल, हरियाणा से संजय भाटिया और त्रिपुरा से बिप्लब देब को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिलना उन राज्यों में विस्तार की जरूरत से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां अगले दौर में चुनाव हैं।

दूसरे दल से आए लोगों को भी मौका : आप से आए संदीप पाठक और कांग्रेस से आए रोहन गुप्ता को सचिव बनाया गया है।

नवीन की टीम में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी व पंजाब से जुड़े वरिष्ठ नेता सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) बनाया गया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक को भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मिली है। मनप्रीत बादल को भाजपा के प्रमुख सिख चेहरे के तौर पर संगठन में जगह दी गई है। इसे पंजाब में सिख समुदाय के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ाने की रणनीति माना जा रहा है।

शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के चचेरे भाई मनप्रीत पांच बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं। तरुण चुघ आरएसएस और एबीवीपी से राजनीतिक सफर शुरू कर भाजपा युवा मोर्चा में भी रहे। सौदान सिंह आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश से संगठनात्मक काम शुरू किया और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व राजस्थान समेत कई राज्यों में भाजपा संगठन को मजबूत करने में भूमिका निभाई।

उत्तराखंड को राष्ट्रीय टीम में तीन प्रतिनिधित्व मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को उपाध्यक्ष, अनिल बलूनी को मीडिया संयोजक और आलोक भट्ट को सोशल मीडिया टीम में सह संयोजक बनाया गया है। यानी राज्य के ब्राह्मण और ठाकुर, दोनों प्रमुख सामाजिक समूहों को जगह मिली है। यह संतुलन उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा के लिए महत्वपूर्ण रहा है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में हरियाणा से जुड़े चार नेताओं को जगह मिली है। राज्यसभा सदस्य व करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया, हरियाणा भाजपा के मौजूदा प्रभारी व राज्यसभा सदस्य सतीश पूनिया को पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्ति किया गया है। भाजपा हरियाणा के पूर्व सोशल मीडिया प्रमुख व गुरुग्राम निवासी अरुण यादव को राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता व गुरुग्राम की पूर्व सांसद डॉ. सुधा यादव के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सिद्धार्थ यादव को मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। हरियाणा के पूर्व प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब को भी राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे जाट नेता ओमप्रकाश धनखड़ को फिलहाल नई टीम में जगह नहीं मिली है।

गोवा और मणिपुर का खाता खाली

दूसरी ओर आगामी चुनाव वाले गोवा और मणिपुर को राष्ट्रीय टीम में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला।दोनों राज्यों का खाता इस बार खाली रहा। यह भी दिलचस्प है कि खुद भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन बिहार से आते हैं, लेकिन नई टीम में बिहार को भी सिर्फ दो चेहरे मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि प्रतिनिधित्व तय करने में अध्यक्ष के गृहप्रदेश से ज्यादा चुनावी जरूरत और सामाजिक समीकरण को महत्व दिया गया है।

किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर निशाना, बोले-

पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान से घबराई कांग्रेस पार्टी

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को कांग्रेस पर माओवादी पार्टी में बदलने का आरोप लगाया। यह आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिमागी नक्सलियों के जिक्र को लेकर मचे राजनीतिक विवाद के बीच लगाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए मोदी

ने कहा कि हालांकि जंगलों में सक्रिय हथियारबंद नक्सलियों को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है, लेकिन देश के अलग-अलग हिस्सों में दिमागी नक्सली अभी भी मौजूद हैं और उन्हें पहचानकर अलग-थलग करने की ज़रूरत है।

इन बयानों की विपक्ष के नेताओं ने आलोचना की; कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने एक्स पर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। मीडिया से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि मोदी की टिप्पणी किसी खास विपक्षी पार्टी के लिए नहीं थी, लेकिन उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेताओं ने मान लिया कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पर ऐसी विचारधारा वाले लोगों का कब्ज़ा था और दावा किया कि अब कांग्रेस माओवाद की ओर बढ़ती दिख रही है।

उन्होंने वैचारिक नक्सलवाद को अलगाववादी सोच और अनुच्छेद 370 को बहाल करने या पूर्वोत्तर को भारत के बाकी हिस्सों से अलग करने जैसी मांगों का समर्थन करने वाला बताया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी माओवादी और नक्सलवादी संगठन में बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी पहले ही मुस्लिम लीग जैसी हो चुकी है और अब माओवादी पार्टी बनने की दिशा में बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मोदी की बातें, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद को एक बड़ा खतरा बताने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आकलन जैसी ही थीं।

रिजिजू ने सिंह के 2006 के उस बयान का ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने नक्सलवाद को देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को मोदी की बातों की आलोचना करने के लिए सिंह के परिवार से माफ़ी मांगनी चाहिए। रिजिजू ने आगे आरोप लगाया कि जिन्हें उन्होंने दिमागी नक्सली कहा, उन्होंने नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए सुरक्षाकर्मियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उनकी मौत का जश्न मनाया।

संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की कांग्रेस की मांग पर रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी संसद का सामना करने से डर गई। इसी वजह से उन्होंने चर्चा से भागने का बहाना बनाया। जब सरकार हर सवाल का जवाब देने और स्थिति व दूसरी सभी जानकारियां समझाने के लिए तैयार थी, तब कांग्रेस पार्टी भागने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सच्चाई का सामना करने की स्थिति में नहीं थी।

गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, हम पहले दिन से कह रहे थे कि हम चर्चा चाहते हैं। लेकिन उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। वे सिर्फ बहाने बना रहे थे। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा, समस्या यह है कि कांग्रेस सांसद और कई दूसरे सांसद मेरे पास आकर कहते हैं कि संसद को चलाने के लिए मैं कुछ करूं। मैं उनसे पूछता हूं- मुझसे क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी से जाकर बात करो। आखिर संसद में कांग्रेस के सदस्य वही करते हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

तेजस्विन-दिव्या-त्रिशा समेत 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड

गॉल। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने

मंगलवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा की। अलग-अलग क्षेत्र के 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं, तीन कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने अलग-अलग श्रेणी में खिलाड़ियों, कोच और संस्थाओं को अवॉर्ड देने का फैसला किया है।

अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), मुहम्मद अजमल वी (एथलेटिक्स), प्रियंका गोस्वामी (एथलेटिक्स), त्रिशा जॉली (बैडमिंटन), पुलेला गायत्री गोपीचंद (बैडमिंटन), नरेंद्र (बॉक्सिंग), विदित गुजराती (शतरंज), दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (बधिर शूटिंग), लालरेमसियामी (हॉकी), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), पूजा (कबड्डी), रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग), एकता भ्यान (पैरा एथलेटिक्स), अरविंद सिंह (रोइंग), अखिल श्योरण (शूटिंग) का नाम चुना गया है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल-भावना और अनुशासन की भावना दिखाने वाले एथलीटों को दिया जाता है।

अर्जुन पुरस्कार (लाइफटाइम) 2025, आई अरुमनायगम (फुटबॉल) को दिया गया है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मान देने और प्रेरित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में योगदान दिया है और खेल से संन्यास के बाद किसी न किसी रूप में जुड़कर उसे बढ़ावा देने में योगदान देते रहते हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्ड 2025, परवीर सिंह (एथलेटिक्स), छोटे लाल यादव (बॉक्सिंग), और नेहा नंदकुमार चव्हाण (शूटिंग) को दिया गया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 492 अंक लुढ़का निफ्टी 24,200 के नीचे

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भी गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 492 अंक से अधिक लुढ़क गया। वहीं, निफ्टी भी 24,200 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के बाद सेंसेक्स 77,235.46 अंक पर बंद हुआ, जिसमें 0.63 फीसदी की गिरावट आई। निफ्टी 132.75 अंक गिरकर 24,154.90 के स्तर पर पहुंच गया। इसमें 0.55 फीसदी की कमी देखी गई। इस गिरावट से निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। बाजार में बिकवाली का दबाव साफ नजर आया। आज के कारोबार में एचसीएल टेक और इंफोसिस जैसी दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में लगभग 2 फीसदी की बड़ी गिरावट आई। इन कंपनियों के शेयरों में आई कमी ने बाजार के नकारात्मक रुख को और बढ़ा दिया। निवेशकों ने इन शेयरों से दूरी बनाई। यह गिरावट बाजार के समग्र प्रदर्शन पर भारी पड़ी।

क्रूड ऑयल का दाम 90 डॉलर के पार निकला

नईदिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में लौटी तेजी से दुनियाभर की टेंशन फिर बढ़ गई है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड का भाव 90 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गया है। फिलहाल 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। पिछले हफ्ते कीमतों में 5-6 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई थी। क्रूड की कीमतों में तेजी के लिए बड़ा ट्रिगर यूएस-ईरान में जारी तनाव है। क्योंकि फाइनल सेटलमेंट के लिए खुला 60 दिनों का विंडो बंद हो गया है। ट्रंप और ईरान के नेताओं में जारी बयानबाजी ने आग घी में डालने का काम किया है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि कीमतें आगे भी ऊंची बनी रह सकती हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही। ब्रेंट क्रूड 91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। पिछले हफ्ते 6 फीसदी की वीकली बढ़त दर्ज की गई थी।

कैश सर्कुलेशन बढ़ने से आरबीआई की करेंसी प्लानिंग चुनौतीपूर्ण

नईदिल्ली। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते इस्तेमाल के बीच लोगों के लेन-देन में कैश का हिस्सा भले ही कम हो रहा है, लेकिन चलन में मौजूद करेंसी की मात्रा दोहरे अंकों की दर से बढ़ रही है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि इस स्थिति के कारण भविष्य में कैश की मांग का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है और आरबीआई के लिए कैश के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता की योजना बनाना भी जटिल हो गया है। मुर्मू ने कहा, पिछले दशक में भारत में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल क्रांतिकारी रहा है, फिर भी चलन में मौजूद कैश में कोई कमी नहीं आई है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में, कम आय वाले लोगों, बुजुर्गों और छोटे व्यवसायों के बीच। मुर्मू ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में, आरबीआई ने हर साल छह अलग-अलग डिनॉमिनेशन के 28 अरब से 30 अरब बैंक नोट छापे हैं।

जीडीपी ग्रोथ वित्तवर्ष-27 में 6.8% रहने का अनुमान

नईदिल्ली। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को अनुमान लगाया कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ धीमी होकर 6.8 प्रतिशत रह जाएगी, जबकि पिछले साल यह 7.6 प्रतिशत थी। एजेंसी ने इसके लिए पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता के कारण ईंधन और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी, कमजोर करेंसी और खेती पर अल-नीनो के संभावित असर जैसे जोखिमों का हवाला दिया। वित्तवर्ष 27 के लिए 6.8 प्रतिशत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मई में लगाए गए 6.7 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है। इस महीने की शुरुआत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए ग्रोथ का अनुमान 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया था।

रोजगार की नई राह बनेगा सेवा क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में छिपी बड़ी संभावनाएं

आर कविता राव

पिछले एक महीने में देशभर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में प्रमुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता की मांग की गई। इसका तात्कालिक कारण नीट-यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र का लीक होना था। लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अन्य कई परीक्षाओं का भी उल्लेख किया।

इसके जवाब में सरकार ने संसद में नया विधेयक पेश किया। सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 नामक इस विधेयक के तहत किसी भी लीक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों पर और कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए), जो नीट और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जैसी महत्त्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित करती है, उसको पुनर्गठित किया जा रहा है और 47 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवाल मूल रूप से निष्पक्षता से जुड़े हैं। पैसों के बदले प्रश्नपत्र बेचे जाने की आशंका पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती है। इसलिए केवल एनटीए ही नहीं बल्कि उन सभी एजेंसियों का पुनर्गठन आवश्यक है जो उच्च शिक्षा कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं आयोजित करती हैं।

इसके साथ ही एक बुनियादी सवाल उठता है। वह यह कि आखिर लीक का बाजार क्यों और कैसे बनता है और टिकता है? शायद इसका उत्तर भारत के रोजगार बाजार की प्रकृति में छिपा हुआ है। आवधिक श्रम शक्ति सर्वे (पीएलएफएस) भारत में नौकरियों की संरचना पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत करता है। वर्ष 2025 में कुल

कार्यबल में नियमित श्रमिकों का हिस्सा 23.6 फीसदी था जिनमें से आधे से अधिक सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत थे। स्वरोजगार करने वालों का हिस्सा आधे से अधिक यानी करीब (56फीसदी) था जबकि शेष अस्थायी श्रमिक थे।

नियमित श्रमिकों का औसत मासिक वेतन लगभग 22,699 रुपये बताया गया जो स्वरोजगार करने वालों की औसत मासिक आय 14,861 रुपये और अस्थायी श्रमिकों की आय 10,000 रुपये (यह मानकर कि वे औसतन वे महीने में 22 दिन काम करते हैं) से अधिक है। नियमित श्रमिकों में भी बड़ा अंतर है। 50 फीसदी से अधिक के पास लिखित अनुबंध नहीं है और न ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है।

विभिन्न गतिविधियों में वेतन के अंतर को समझने के लिए सर्वेक्षण ने कई व्यवसायिक वर्गीकरण दिए हैं। नियमित श्रमिकों में सबसे अधिक और सबसे कम वेतन का अनुपात 4:1 है। यदि सबसे अधिक वेतन पाने वाले नियमित श्रमिकों की तुलना अस्थायी श्रमिकों से की जाए तो अंतर 7: 4 गुना है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में विशेषकर निचले स्तर की नौकरियों में ज्यादा वेतन मिलता है। दूसरी ओर स्वरोजगार करने वालों की श्रेणी में कई अवैतनिक पारिवारिक कामगार शामिल हैं। भारत में अच्छी वेतन वाली नौकरियों की कमी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में वेतन अधिक होने के कारण इन नौकरियों की मांग अधिक है और लोग इनमें किसी भी तरह से शामिल होना चाहते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अवसर मिलने पर अपने पक्ष में तराजू झुकाने को तैयार रहते हैं। पेपर लीक को प्रोत्साहन यहीं से मिलता है। इसलिए जहां अल्पकालिक समाधान प्रस्तावित कानून और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों का पुनर्गठन है वहीं हमें यह भी देखना होगा कि अर्थव्यवस्था कितनी नौकरियां पैदा कर रही है ताकि मूल कारण का समाधान हो सके। देश में रोजगार सृजन की अर्थव्यवस्था पिछले वर्षों में काफी बदल गई है। केएलईएमएस डेटाबेस बताता है कि पूंजी की प्रति इकाई पर श्रम का अनुपात समय के साथ सभी प्रमुख क्षेत्रों में लगातार घटा है। यानी आर्थिक गतिविधियां समय के साथ अधिक पूंजी-गहन होती जा रही हैं। कृषि और संबद्ध सेवाओं में यह अनुपात बाकी अर्थव्यवस्था की तुलना में अधिक है लेकिन विनिर्माण और सेवाओं में यह अनुपात तेजी से एक समान हो रहा है।

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

शिक्षा में विकास रोजगार–करियर में भविष्य गढ़ता छत्तीसगढ़

युवा शक्ति, आधुनिक शिक्षा और रोजगार के अवसरों से विकसित छत्तीसगढ़ की नई उड़ान

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ आज केवल प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का प्रदेश नहीं रह गया है, बल्कि वह तेजी से ज्ञान, कौशल, नवाचार और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शिक्षा, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन और रोजगार सृजन को एकीकृत करते हुए युवाओं के लिए अवसरों का ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है, जो उन्हें स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक प्रतिस्पर्धी बना रहा है।

नई शिक्षा नीति, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना, अटल करियर निर्माण योजना, डिजिटल रोजगार सेवाएं, मॉडल करियर सेंटर, बेरोजगारी भत्ता योजना, उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार, नवा रायपुर आईटी हब और नई औद्योगिक नीति जैसी पहलों ने राज्य के युवाओं को रोजगार सृजित करने वाला बनाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया है। आज छत्तीसगढ़ का युवा पारंपरिक डिग्री से आगे बढ़कर कौशल, नवाचार, स्टार्टअप, तकनीक और वैश्विक करियर की ओर कदम बढ़ा रहा है।

आज छत्तीसगढ़ का युवा पारंपरिक डिग्री से आगे बढ़कर कौशल, नवाचार, स्टार्टअप, तकनीक और वैश्विक करियर की ओर कदम बढ़ा रहा है।
यही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है।

1 उत्कृष्टता केंद्र योजनाः कॉलेजों को बनाया जा रहा भविष्य का करियर लॉन्चपैड

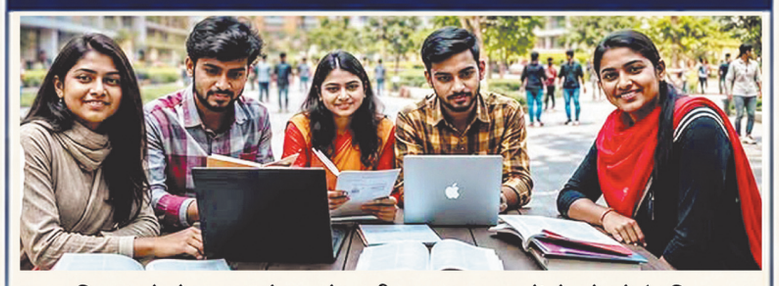

उच्च शिक्षा को रोजगार और उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र (Center of Excellence) योजना प्रारंभ की है। इसके तहत राज्य के प्रमुख महाविद्यालयों को आधुनिक संसाधनों और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है।

- अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ और स्मार्ट क्लासरूम
- डिजिटल लर्निंग सेंटर और ई-लाइब्रेरी
- रिसर्च एवं इनोवेशन लैब और स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेल
- करियर गाइडेंस और प्लेसमेंट सहायता

इस पहल से ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी वैश्विक स्तर के अवसर उपलब्ध हो रहे है और शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई कम हो रही है।

2 अटल करियर निर्माण योजनाः श्रमिक परिवारों के सपनों को मिल रही नई दिशा

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल करियर निर्माण योजना आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है।

- JEE Main, JEE Advanced, CGPET, NEET-UG की नि :शुल्क कोचिंग
- अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिस मॉडयुल, पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट, छात्रावास और भोजन की सुविधा
- गैर आवासीय विद्यार्थियों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर 5,000 रुपए तक मासिक सहायता
- 50 प्रतिशत सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित

यह योजना बेटियों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को नई उड़ान दे रही है।

3 विश्वविद्यालयों को नई ताकतः उच्च शिक्षा से ग्लोबल करियर की ओर

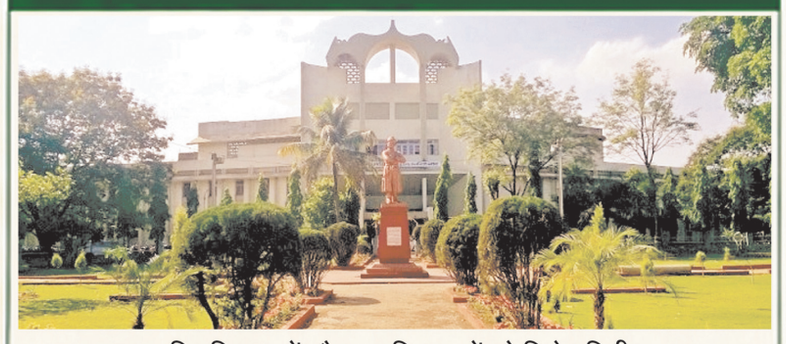

राज्य सरकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। नए भवन, आधुनिक प्रयोगशालाएं, शोध सुविधाएं और डिजिटल अवसंरचना से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल रहा है।

- विश्वविद्यालयों को करोड़ों के अनुदान
- रिसर्च एवं इनोवेशन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रोत्साहन
- स्थानीय समस्याओं के समाधान और स्टार्टअप को बढ़ावा

छत्तीसगढ़ को ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में निर्णायक कदम।

संवाद-48628/1

4 रोजगार के नए द्वारः निवेश, उद्योग और आईटी सेक्टर से बढ़ते अवसर

- नई औद्योगिक नीति से युवाओं के लिए बढ़े अवसर
- 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना
- करीब 5 लाख नए रोजगारों का सृजन
- नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है
- आईटी कंपनियों और उद्योगों से उच्च वेतन वाले रोजगार उपलब्ध

छत्तीसगढ़ का युवा अब अपने राज्य में ही आधुनिक और वैश्विक स्तर के करियर विकल्प प्राप्त कर रहा है।

5 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन

- UPSC, CGPSC और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष सहयोग
- दिल्ली के द्वारका स्थित ट्राइवल यूथ हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर 185 सीट
- आदिवासी और दुर्स्स्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण तैयारी के लिए बेहतर सुविधा

6 मॉडल करियर सेंटरः करियर मार्गदर्शन का आधुनिक नेटवर्क

- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, कांकेर सहित अनेक जिलों में मॉडल करियर सेंटर
- करियर परामर्श, प्लेसमेंट सहायता, रोजगार सुचना और कौशल प्रशिक्षण
- उद्योगों और युवाओं के बीच सीधा संपर्क, अधिक रोजगार अवसर

7 ई-रोजगार पोर्टल : डिजिटल तकनीक से रोजगार तक सीधी पहुंच

- ऑनलाइन पंजीयन, नवीनीकरण, रोजगार मेलें, सक्रिय रिक्तियों, अप्रेंटिसशिप अवसर और करियर मार्गदर्शन
- सभी 33 जिलों की रोजगार सेवाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी
- आधार आधारित आवेदन प्रक्रिया, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा

8 युवा शक्ति बनेगी विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत

- युवा नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बनें।
- विकसित भारत-2047 में छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की निर्णायक भूमिका होगी।
- शिक्षा, कौशल, नवाचार और उद्यमिता से आत्मनिर्भर एवं विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।

“ छत्तीसगढ़ के युवाओं में अपार प्रतिभा

छत्तीसगढ़ के युवाओं में प्रतिभा, ऊर्जा और नवाचार की अपार क्षमता है। हमारी सरकार का लक्ष्य उन्हें आधुनिक शिक्षा, तकनीकी कौशल, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। हम ऐसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, जहाँ युवा केवल रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बने। उत्कृष्ट शिक्षा, कौशल विकास, उद्योग निवेश और डिजिटल अवसरों के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की सबसे बड़ी आधारशिला बनेगी।

-विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ ”

शिक्षा, कौशल विकास, करियर मार्गदर्शन, डिजिटल रोजगार सेवाएं, उच्च शिक्षा विस्तार, प्रतियोगी परीक्षा सहायता, औद्योगिक निवेश और आर्थिक संबल जैसी बहुआयामी पहलों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं के भविष्य को नई दिशा दे रही है।

आज राज्य में शिक्षा से कौशल, कौशल से रोजगार और रोजगार से आत्मनिर्भरता की मजबूत श्रृंखला विकसित हो रही है। यही प्रयास छत्तीसगढ़ को ज्ञान, नवाचार और अवसरों के नए युग की ओर ले जा रहे हैं।

शिक्षा से ज्ञान • कौशल से आत्मविश्वास • रोजगार से समृद्धि • नवाचार से विकसित छत्तीसगढ़

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.